RNI No. DELHIN/2012/48773 विशेषांक 2026 वर्ष 14, अंक 11 ₹100

फेम इंडिया

सोच बदलें, समाज बदलेगा



सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री 2026



व्यक्तित्व - अविनाश रंजन झा

फेम इंडिया -एशिया पोस्ट सर्वे



फेम इंडिया

www.thefameindia.com

वर्ष 14, अंक 11, नवंबर 2026

एडिटर इन चीफ – धीरज कुमार
मैनेजिंग एडिटर – अनिल सिंह

असिस्टेंट एडिटर – मनीष सिंह

एडिटोरियल टीम –
दिलीप सिंह, श्वेता जया, राकेश चौधरी, नीलम शुक्ला, सुनील सिंह, नम्रता नारायण, कल्पना पुंडीर, विजय पांडेय, अमरनाथ, हेमंत सिंह, रोहित रोहण, विकास सिंह, नीरज सहाय, सुधा पांडेय, संतोष कुमार सिंह, संजय बाली

संपादकीय सलाहकार – अतुल सिंघल

कोऑर्डिनेटर – देवेश मिश्रा

आर्ट डायरेक्टर – स्वर्ण लता

वेब टीम – मानवेंद्र प्रताप, रश्मि सिंह

सेल्स – अनामिका गौतम
मार्केटिंग – सुनील पुंडीर
सर्कुलेशन – प्रवीण मिश्रा

कानूनी सलाहकार
अमित खेमका

(स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक राजश्री द्वारा ज्योति प्रिंटर्स, ई-94, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर से मुद्रित एवं ए-533, जीडी कालोनी, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली से प्रकाशित, संपादक – धीरज कुमार)

संपादकीय एवं मार्केटिंग ऑफिस
फेम इंडिया पब्लिकेशन प्रा.लि.
एफ 6, सेक्टर-50, नोएडा 201304 (उ.प्र.)
फोन नं. – +91- 9717727501 / 9451587800 / 0120 315 4572
ई मेल: fameindia.publication@gmail.com

RNI No. DELHIN/2012/48773

संपादकीय

सुशासन की कसौटी पर नेतृत्व: सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री सर्वे 2026

लोकतंत्र में जनता का विश्वास किसी भी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और राज्यों में इस विश्वास की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधों पर होती है। सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे सवालों का जवाब आखिरकार उसी कुर्सी से अपेक्षित होता है। इसी भावना के साथ फेम इंडिया और एशिया पोस्ट ने 'सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री सर्वे 2026' कराया, जिसके परिणाम अब आपके सामने हैं।

इस सर्वे की विशेषता इसकी बहुस्तरीय पद्धति है। सोशल मीडिया और मीडिया में जनधारणा का अध्ययन, प्रबुद्धजनों की राय और आम लोगों से सीधा संवाद, इन तीनों को मिलाकर सुशासन, विधि-व्यवस्था, पारदर्शिता और कार्यशैली जैसे दस मानदंडों पर 1000 अंकों में आकलन किया गया। इस तरह यह रैंकिंग केवल लोकप्रियता नहीं, बल्कि कार्य और परिणामों को भी कसौटी बनाती है।



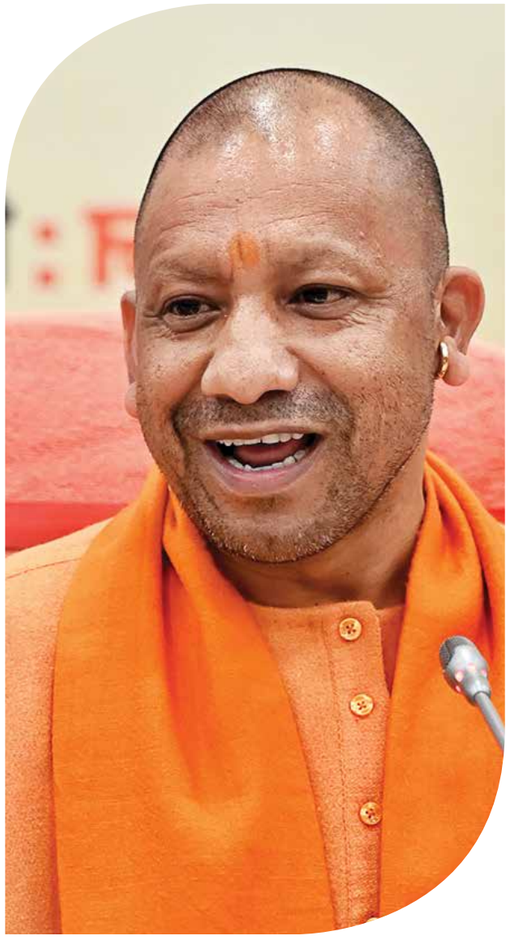
इस सर्वेक्षण का उद्देश्य केवल किसी मुख्यमंत्री को पहला, दूसरा या तीसरा स्थान देना नहीं है। इसका व्यापक लक्ष्य राज्यों के नेतृत्व के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और बेहतर शासन की भावना को प्रोत्साहित करना है। रैंकिंग में स्थान पाने वाले मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धियों और कार्यशैली को पहचान दिलाने का अवसर मिलेगा। वहीं, अपेक्षाकृत पीछे रहने वाले नेतृत्वकर्ताओं के लिए यह आत्ममंथन और सुधार का एक संकेत बन सकता है। अगला लक्ष्य जवाबदेही की संस्कृति को बल देना है। जब नेतृत्व जानता है कि उसके कार्यों का निष्पक्ष और सार्वजनिक आकलन होता है, तो पारदर्शिता और परिणामोन्मुख कार्यशैली को प्रोत्साहन मिलता है।

हमें अपेक्षा है कि यह सर्वे नीति-निर्माताओं और प्रशासनिक तंत्र को अपनी शक्तियों और कमियों का आईना दिखाएगा। मानदंडवार अंक यह संकेत देते हैं कि कहां बेहतर प्रदर्शन हुआ और कहां सुधार की गुंजाइश है। इससे राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिसका लाभ अंततः नागरिकों को मिलेगा। शोधकर्ताओं, मीडिया और जागरूक पाठकों के लिए यह सर्वे चर्चा और अध्ययन का एक ठोस आधार भी बनेगा। साथ ही 'मुख्यमंत्री पंचरत्न' जैसी श्रेणी उन नेताओं को भी मंच देती है, जो शीर्ष दस के निकट रहकर अपनी पहचान बना रहे हैं।

हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सर्वेक्षण किसी सरकार या राजनीतिक दल के पक्ष अथवा विपक्ष में अभियान नहीं है। यह एक स्वतंत्र मूल्यांकन का प्रयास है, जिसकी सार्थकता निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है।

सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने वाले सभी मुख्यमंत्रियों को हमारी शुभकामनाएं। असली जीत तब होगी, जब रैंकिंग से अधिक राज्यों के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर दिखेगी।

धीरज



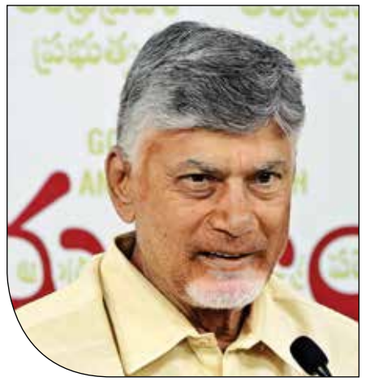




























फेम इंडिया–एशिया पोस्ट 'सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री सर्वे 2026'

किसी भी राज्य की प्रगति, सुरक्षा और जनकल्याण की दिशा तय करने में मुख्यमंत्री की भूमिका सबसे अहम होती है। उनके निर्णयों का असर कानून-व्यवस्था, विकास, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और आम नागरिक के जीवन पर सीधे पड़ता है। इसी सोच के साथ फेम इंडिया मैगजीन ने देश की प्रमुख सर्वे एजेंसी एशिया पोस्ट के सहयोग से 'सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री सर्वे 2026' का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्रियों के कार्यों, प्रशासनिक दृष्टिकोण और उपलब्धियों का निष्पक्ष और व्यापक मूल्यांकन करना है।

लगभग तीन से चार महीने चले इस सर्वेक्षण को तीन स्तरों पर संचालित किया गया। पहले स्तर पर सोशल मीडिया और सामान्य मीडिया में उपलब्ध प्रतिक्रियाओं, समाचारों और जनधारणा का अध्ययन हुआ। दूसरे स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों और प्रबुद्धजनों की राय शामिल की गई।



तीसरे स्तर पर आम लोगों से सीधा संवाद कर उनके अनुभव और विचार जाने गए। इन तीनों स्तरों से मिली जानकारी के समग्र विश्लेषण के आधार पर मुख्यमंत्रियों को परखा गया।

मूल्यांकन के लिए दस प्रमुख मानदंड तय किए गए: सुशासन, विधि-व्यवस्था, व्यक्तित्व, छवि, कार्यक्षमता, प्रभाव, विभागों की समझ, लोकप्रियता, दूरदर्शिता तथा कार्यशैली एवं परिणाम। प्रत्येक मानदंड पर मिले अंकों को जोड़कर 1000 अंकों की प्रणाली में अंतिम स्कोर और रैंकिंग तैयार की गई। इस प्रक्रिया का लक्ष्य केवल लोकप्रियता नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता और शासन के नतीजों की संपूर्ण तस्वीर सामने लाना है।

सर्वेक्षण में कुल 15 मुख्यमंत्रियों को स्थान मिला है। शीर्ष दस मुख्यमंत्रियों को 'सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री' और 11वें से 15वें स्थान के पांच मुख्यमंत्रियों को विशेष श्रेणी 'मुख्यमंत्री पंचरत्न' के रूप में चुना गया है। अंतिम परिणामों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1000 में से 897 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 881 अंकों के साथ दूसरे और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा 874 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

फेम इंडिया–एशिया पोस्ट की यह पहल उन नेतृत्वकर्ताओं के कार्यों और उपलब्धियों को सामने लाने का प्रयास है, जो अपने राज्यों की प्रशासनिक और विकासात्मक दिशा को प्रभावित कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य बेहतर शासन, जवाबदेही, जनोन्मुख प्रशासन और परिणाम आधारित नेतृत्व को प्रोत्साहित करना है। यह सर्वेक्षण देश के राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व का एक तुलनात्मक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, साथ ही इस महत्वपूर्ण सवाल पर भी ध्यान आकर्षित करता है कि आखिर एक बेहतर मुख्यमंत्री की पहचान किन गुणों और कार्यों से बनती है।

-अनिल सिंह



1

जब भी देश में कायाकल्प की बात होती है, तो सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का सामने आता है जो अब उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है, और राज्य के बदलाव की कथा में एक नाम जो सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है वह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस राज्य की पहचान कभी अपराध, अराजकता और प्रशासनिक अव्यवस्था से जुड़ी थी, वही उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे तेज़ी से बदलते राज्यों में शुमार हो चुका है। यह बदलाव अचानक नहीं आया — यह एक दृढ़ नेतृत्व, स्पष्ट नीति और निरंतर क्रियान्वयन का परिणाम है। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ शासन नहीं चलाया, बल्कि सूबे को एक नई पहचान दी।

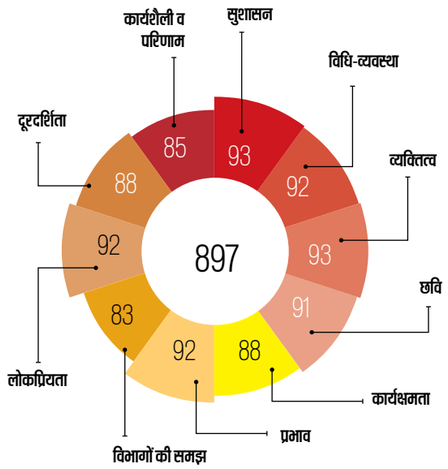
उत्तर प्रदेश के कायाकल्प का नायक

योगी आदित्यनाथ

एक नए युग की शुरुआत



2016 की तुलना में डकैती में 84.75%, लूट में 82.75%, हत्या में 44.75% और बलात्कार की घटनाओं में 58.17% की कमी — ये आंकड़े किसी नारे का नहीं, बल्कि जमीनी कार्रवाई का प्रमाण हैं। हाल के वर्ष में भी यह सतर्कता जारी रही — जनवरी 2023 से जून 2026 तक सोशल मीडिया पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट का संज्ञान लेकर मेटा के सहयोग से 3,295 लोगों की जान बचाई गई, जो दिखाता है कि योगी सरकार अब पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़कर तकनीक-संचालित सुरक्षा मॉडल की ओर बढ़ चुकी है।



कानून-व्यवस्था: निर्भीक नेतृत्व की मिसाल

योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है — अपराध और अपराधियों के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस नीति। 2017 से अब तक राज्य में एक भी सांप्रदायिक दंगा या जातिगत संघर्ष दर्ज नहीं हुआ — यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई में 303 अपराधी मुठभेड़ों में ढेर हुए, 23,601 इनामी अपराधी जेल भेजे गए, और 87,835 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत शिकंजा कसा गया। माफिया तंत्र को उखाड़ फेंकने के अभियान में 68 चिन्हित माफिया गिरोहों पर कार्रवाई करते हुए 4,309 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई, और 36 माफिया व 104 संगठित अपराधियों को आजीवन कारावास दिलाया गया।

बुनियादी ढांचे की क्रांति

जहां पुरानी सरकारों के दौर में उत्तर प्रदेश सड़कों और संपर्क के मामले में पिछड़ा माना जाता था, वहीं आज यह देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य बन चुका है। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 302 किलोमीटर का आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे — ये सभी योगी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं। वर्तमान में 10 एक्सप्रेसवे पूरी तरह संचालित हैं, जबकि गोरखपुर-शामली (700 किमी), गोरखपुर-सिलीगुड़ी (519 किमी) और विंध्य एक्सप्रेसवे (320 किमी) सहित 12 और एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन या प्रस्तावित चरण में हैं।

हवाई संपर्क में भी उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है। प्रदेश आज देश का सर्वाधिक हवाई अड्डों वाला राज्य है, जहां 17 एयरपोर्ट में से पांच अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं — लखनऊ, कुशीनगर, वाराणसी, अयोध्या और जेवर। लगभग 16,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क, 90 राष्ट्रीय राजमार्गों और दादरी में स्थित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जंक्शन ने राज्य को उत्तर भारत का लॉजिस्टिक्स हब बना दिया है।

अयोध्या से काशी तक: आस्था का आर्थिक रूपांतरण

योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक पर्यटन को केवल आस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आर्थिक शक्ति में बदल दिया। पिछले एक वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि रहा 2025 का महाकुंभ, जिसमें अकेले उस वर्ष 156.18 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश पहुंचे — यह आंकड़ा अपने आप में विश्व इतिहास की





औद्योगिक विस्तार: हर क्षेत्र को अवसर

योगी सरकार ने राज्य के हर हिस्से में विशेष औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार किए हैं — ग्रेटर नोएडा में आईआईटीजीएनएल, बरेली में मेगा फूड पार्क, गोरखपुर में प्लास्टिक व गारमेंट पार्क, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फिल्म सिटी और टॉय पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, तथा जेवर क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत लखनऊ-हरदोई में निर्माणाधीन मेगा टेक्सटाइल पार्क से तीन लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। साथ ही, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 13 अधिनियमों में लगभग 99% छोटे आपराधिक प्रावधान समाप्त किए गए — यह सुधारवादी दृष्टिकोण का प्रमाण है।

सबसे बड़ी मानव सभा का प्रमाण है। 2017 में जहां प्रदेश में मात्र 23.75 करोड़ पर्यटक आते थे, वहीं 2024 में यह संख्या 64.91 करोड़ तक पहुंच गई — यानी नौ वर्षों में लगभग सात गुना वृद्धि, और राष्ट्रीय पर्यटन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी अब 21.9 प्रतिशत हो चुकी है।

इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, 2026-27 के बजट में योगी सरकार ने अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के लिए 150 करोड़ रुपये, नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के लिए 100 करोड़ रुपये तथा विंध्यवासिनी देवी धाम और वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के लिए 100-100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है — यह दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता केवल आयोजन तक सीमित नहीं, बल्कि दीर्घकालिक अवसंरचना निर्माण की है। अयोध्या, देवीपाटन, ब्रज तीर्थ, विंध्याचल, चित्रकूट, नैमिषारण्य और शुक्रतीर्थ के लिए सात विकास परिषदें तथा रामायण, कृष्ण, बौद्ध, जैन, सूफी और स्वतंत्रता संग्राम सर्किट सहित 12 से अधिक टूरिस्ट सर्किट इस विजन को साकार कर रहे हैं।

निवेश के नए कीर्तिमान

आर्थिक मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। नौ वर्षों में राज्य को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निजी निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.10 करोड़ रोजगार सृजित होने की संभावना है। पिछले एक वर्ष की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि रही विश्व आर्थिक मंच (WEF) 2026, जहां उत्तर प्रदेश ने एआई, डेटा सेंटर, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा विनिर्माण जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में 2,94,255 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए — यह प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर वैश्विक टेक्नोलॉजी और नवाचार के मानचित्र पर अपनी जगह बना रहा है। इसी दौर में फार्माकॉन्क्लेव 1.0 में बायोजेंटा, शुक्रा फार्मास्यूटिकल्स और अरना फार्मा जैसी कंपनियों के साथ 10,000 करोड़ रुपये के एमओयू हुए।

अब तक चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं, जिनसे 60 लाख रोजगार सृजित हुए हैं, और 7.5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के साथ पांचवीं सेरेमनी प्रस्तावित है — यह निरंतरता दिखाती है कि योगी सरकार के लिए निवेश केवल घोषणा नहीं, बल्कि क्रियान्वयन का विषय है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के तहत पांच वर्षों का 20,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य मात्र तीन वर्षों में हासिल कर लिया गया, जो नीति और गति दोनों की सफलता को रेखांकित करता है।

एक नायक की विकास गाथा

योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है — यह एक ऐसे संकल्प की कहानी है जिसने कानून-व्यवस्था को निवेश से, एक्सप्रेसवे को उद्योग से, और आस्था को अर्थव्यवस्था से जोड़ा। सुरक्षा की मजबूत नींव पर खड़ा उत्तर प्रदेश आज बुनियादी ढांचे, निवेश और पर्यटन के हर मोर्चे पर नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पिछला एक वर्ष इस बात का प्रमाण है कि यह यात्रा और तेज़ हो रही है — महाकुंभ का ऐतिहासिक आयोजन, WEF में रिकॉर्ड निवेश और बजट में धार्मिक स्थलों के लिए बढ़ता आवंटन, यह सब दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब केवल आबादी के लिहाज से नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और अवसरों के लिहाज से भी देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है।



2

उत्तराखंड, जिसकी पहचान वर्षों से पलायन, दुर्गम भूगोल और सीमित संसाधनों की चुनौतियों से जुड़ी रही, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक नई तस्वीर गढ़ रहा है। धामी सरकार की खासियत यह रही है कि उसने केवल घोषणाओं तक सीमित रहने के बजाय ऐसे साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिन्हें लागू करना राजनीतिक रूप से आसान नहीं था — चाहे वह समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन हो, भूमि कानून में सख्ती हो या भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की गारंटी। पर्वतीय राज्य की अपनी सीमाओं के बावजूद, धामी सरकार ने बुनियादी ढांचे, निवेश, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और डिजिटल गवर्नेंस के हर मोर्चे पर तेज़ी दिखाई है।

पहाड़ के हौसलों का नया चेहरा

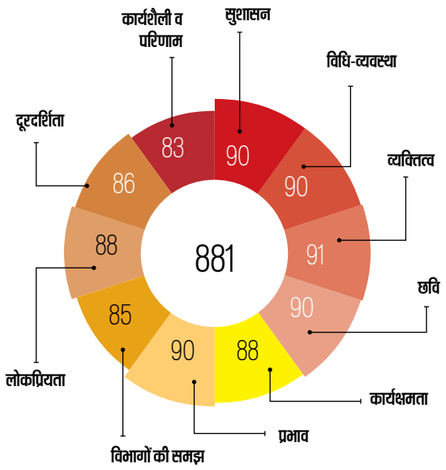
पुष्कर सिंह धामी

चुनौतियों के बीच एक नई राह



भूमि की रक्षा: पहाड़ की पहचान बचाने का संकल्प

उत्तराखंड में बाहरी राज्यों द्वारा भूमि की अंधाधुंध खरीद को लेकर लंबे समय से चिंता रही है। धामी सरकार ने 2025 में भूमि कानून में निर्णायक बदलाव करते हुए राज्य के 11 पर्वतीय जिलों में बाहरी लोगों द्वारा कृषि व उद्यान भूमि की खरीद पर रोक लगाई। यह फैसला दिखाता है कि सरकार केवल निवेश आकर्षित करने की होड़ में स्थानीय पहचान और पर्वतीय संस्कृति को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहती — विकास और संरक्षण के बीच यही संतुलन धामी की नीति निर्माण शैली की पहचान बन चुका है।



यूसीसी: वह फैसला जो इतिहास बना

पुष्कर सिंह धामी सरकार की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का क्रियान्वयन। 27 जनवरी 2025 से लागू इस व्यवस्था के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जहां दशकों से अटकी एक राष्ट्रीय बहस को धरातल पर उतारा गया। विवाह, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे संवेदनशील विषयों पर एक समान कानूनी ढांचा बनाना कोई आसान निर्णय नहीं था, लेकिन धामी ने इसे राजनीतिक साहस के साथ लागू करके दिखाया। विवाह और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल विकसित करना यह दर्शाता है कि सरकार ने नीति को कागज़ी दस्तावेज़ तक सीमित न रखकर एक सुलभ प्रशासनिक तंत्र में बदल दिया।

युवाओं का भरोसा: पारदर्शी भर्ती की गारंटी

उत्तराखंड में सरकारी नौकरी हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रही है, और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर युवाओं में गहरी नाराज़गी भी रही है। इसी पृष्ठभूमि में धामी सरकार ने सख्त एंटी-चीटिंग कानून लागू कर भ्रष्टाचारियों को सख्त संदेश दिया है। बीते पांच वर्षों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिली। साथ ही स्टार्टअप नीति, होमस्टे योजना और सौर स्वरोजगार जैसी पहलों के जरिए रोजगार का दायरा सरकारी नौकरियों से आगे बढ़कर उद्यमिता तक फैलाया गया है।

निवेश जो कागज़ों से धरातल तक पहुंचा

2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तराखंड को 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले थे, और सरकार की सफलता यह रही कि इसमें से लगभग एक लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव वास्तविक धरातल पर उतर चुके हैं — जुलाई 2025 के उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल में इसी उपलब्धि को औपचारिक रूप से रेखांकित किया गया। इन निवेशों से 81 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए, जबकि सहायक उद्योगों के माध्यम से लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त रोजगार की संभावना जताई गई है। महत्वपूर्ण यह भी है कि सरकार निवेश को देहरादून जैसे बड़े शहरों तक सीमित न रखकर टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है।

पहाड़ों तक पहुंचती कनेक्टिविटी

पर्वतीय राज्य के लिए सड़क और रेल संपर्क केवल सुविधा नहीं, आर्थिक और सामरिक ज़रूरत है। 12,000 करोड़ रुपये से



पेयजल और जल संरक्षण: भविष्य की तैयारी

नवंबर 2025 में उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 8,140 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास हुआ, जिनमें देहरादून के लिए सोंग नदी पेयजल परियोजना (2,520.86 करोड़ रुपये, प्रतिदिन 150 मिलियन लीटर जलापूर्ति) और नैनीताल क्षेत्र की जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना (3,678.23 करोड़ रुपये, जून 2029 तक पूर्ण) शामिल हैं। इसके साथ ही स्प्रिंग्स एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी के माध्यम से 5,428 जलस्रोतों और 228 नदियों के पुनर्जीवन का कार्य चल रहा है।

अधिक की चारधाम ऑल-वेदर रोड परियोजना ने पहाड़ों में यात्रा को काफी आसान बनाया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे (लागत 4,081 करोड़ रुपये) और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर रोपवे (लागत 2,730 करोड़ रुपये) की आधारशिला रखी जा चुकी है, जो तीर्थयात्रियों के समय और शारीरिक कठिनाई को काफी कम करेंगे। बद्रीनाथ को स्मार्ट आध्यात्मिक पहाड़ी शहर के रूप में विकसित करने पर 2,255 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का 72.5 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, और केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तराखंड को रेलवे के लिए 4,769 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है।

राज्य में 3.50 लाख करोड़ रुपये की कुल निवेश वाली 42 परियोजनाएं सक्रिय निगरानी में हैं, जिनमें से 1.22 लाख करोड़ रुपये की 15 हाई-वैल्यू परियोजनाएं PRAGATI तंत्र के तहत सीधे ट्रैक की जा रही हैं — यह दर्शाता है कि सरकार परियोजनाओं की घोषणा के बाद उनके वास्तविक क्रियान्वयन पर भी उतनी ही गंभीरता बरतती है।

स्वास्थ्य और महिला सशक्तीकरण: हर घर तक पहुंच

अटल आयुष्मान योजना के तहत उत्तराखंड में 61 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, और 17 लाख से अधिक मरीजों को 3,400 करोड़ रुपये से अधिक का कैशलेस उपचार मिला है। महिला सशक्तीकरण भी धामी सरकार की रणनीति का महत्वपूर्ण आधार बना है — राज्य में 2.54 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।



सीमावर्ती गांव: सुरक्षा और विकास का संगम

वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के अंतर्गत 51 सीमावर्ती गांवों को योजनाबद्ध विकास के लिए चुना गया है, जहां करीब 270 करोड़ रुपये से लगभग 200 विकास परियोजनाओं में निवेश किया जा रहा है। उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां सीमावर्ती गांव देश की पहली सुरक्षा पंक्ति भी हैं, इन समुदायों को मजबूत करना विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

पर्यटन, कृषि और हरित ऊर्जा का नया मॉडल

चारधाम यात्रा को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण, यात्रा प्रमाणपत्र, वाहन पंजीकरण, हेलीकॉप्टर बुकिंग और स्वास्थ्य पंजीकरण जैसी सुविधाओं को एक मंच पर एकीकृत किया। होमस्टे योजना ने स्थानीय रोजगार बढ़ाने के साथ रिवर्स माइग्रेशन को भी प्रोत्साहित किया है। कृषि क्षेत्र में मंडुआ, झंगोरा जैसी पारंपरिक फसलों के साथ हाई-डेंसिटी सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली बागवानी को बढ़ावा दिया गया है। सितंबर 2025 में नाबार्ड ने शिक्षा और डेयरी क्षेत्र की तीन परियोजनाओं के लिए 92.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। हरित ऊर्जा के मोर्चे पर राज्य में 45.175 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र संचालित हैं और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की योजना भी तैयार हो रही है।

प्रशासन जो जनता के द्वार तक पहुंचा

धामी सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष ज़ोर दिया है — 'अपुणि सरकार' पोर्टल के माध्यम से 923 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया है, और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 व भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन 1064 सक्रिय हैं। अधिकारियों को सीधे जनता के बीच भेजा गया, और इसी दौरान देहरादून में 219 करोड़ रुपये की 51 परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास हुआ।

घोषणाओं से क्रियान्वयन तक की यात्रा

पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व उन कठिन फैसलों का प्रतीक है जिन्हें लेना आसान नहीं था। उनके हर फैसले में एक स्पष्ट दृष्टि झलकती है। पहाड़ के हौसलों को नई उड़ान देने की यह कोशिश, आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को देश के सबसे तेज़ी से बदलते राज्यों में शुमार कर सकती है।



3

भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से अलग-थलग माना जाता रहा। लेकिन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम ने वह तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। चाय के बागानों की पहचान रखने वाला यह राज्य आज सेमीकंडक्टर चिप निर्माण, बड़े पैमाने के निवेश और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए पहचाना जा रहा है। हाल ही में सरमा ने स्वयं इस बदलाव को रेखांकित करते हुए बताया कि पिछले एक दशक में असम की अर्थव्यवस्था लगभग तीन गुनी हो चुकी है — यह किसी एक नेता के दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास का ही परिणाम माना जा रहा है।

पूर्वोत्तर भारत के नए विकास नायक

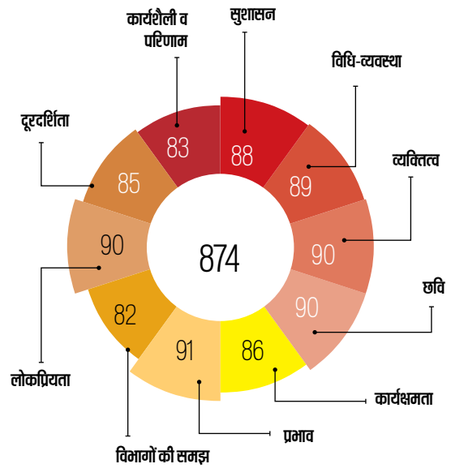
हिमंता बिस्वा सरमा

असम की बदली तस्वीर



पूर्वोत्तर के 'ग्रोथ इंजन' का सपना

सरमा का दीर्घकालिक विजन असम को केवल एक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि समूचे पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक इंजन के रूप में स्थापित करने का है। नई सरकार बनते ही उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेशी निवेश और उद्योगों को आकर्षित कर असम को यह भूमिका दिलाने की दिशा में काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की योजनाएं भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।



जनादेश का तीसरा कीर्तिमान

2026 के असम विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने विकास, कानून-व्यवस्था और मजबूत संगठनात्मक रणनीति के दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की, और कांग्रेस को राज्य के इतिहास में उसकी सबसे कम सीटों पर सीमित कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों की राय में इस ऐतिहासिक जीत के पीछे सरमा की नेतृत्व क्षमता और चुनावी रणनीति की निर्णायक भूमिका रही। तीसरी बार शपथ लेने के तुरंत बाद सरमा ने स्पष्ट कर दिया कि चुनावी घोषणापत्र और जनता से किए वादों को धरातल पर उतारना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, और कानून-व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर विशेष जोर दिया गया।

असम: भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का नया केंद्र

पिछले एक वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धियों में असम का सेमीकंडक्टर संयंत्र सबसे आगे खड़ा है। लगभग 27,000 करोड़ रुपये की लागत से टाटा समूह द्वारा स्थापित किया जा रहा यह संयंत्र देश की चिप निर्माण रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वयं इस परियोजना स्थल का दौरा कर इसे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मुख्यमंत्री सरमा ने इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकनीकी आत्मनिर्भरता की परिकल्पना से जोड़ते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की धुरी हैं, और इस सुविधा के जरिए असम भारत के उन्नत विनिर्माण अभियान के केंद्र में आ जाएगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उच्च-कौशल प्रतिभा के लिए स्थानीय व्यावसायिक इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। सरमा के ही शब्दों में असम अब "चाय से लेकर चिप तक" की पहचान बना चुका है — यह वाक्य उनके कार्यकाल के परिवर्तनकारी स्वभाव को बखूबी दर्शाता है।

निवेश की नई लहर

आर्थिक मोर्चे पर सरमा सरकार ने असम को निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। हाल ही में सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर विजन की घोषणा की, जिसमें कैंसर देखभाल सुविधाओं के विस्तार सहित कई



सुशासन और पारदर्शिता की मिसाल

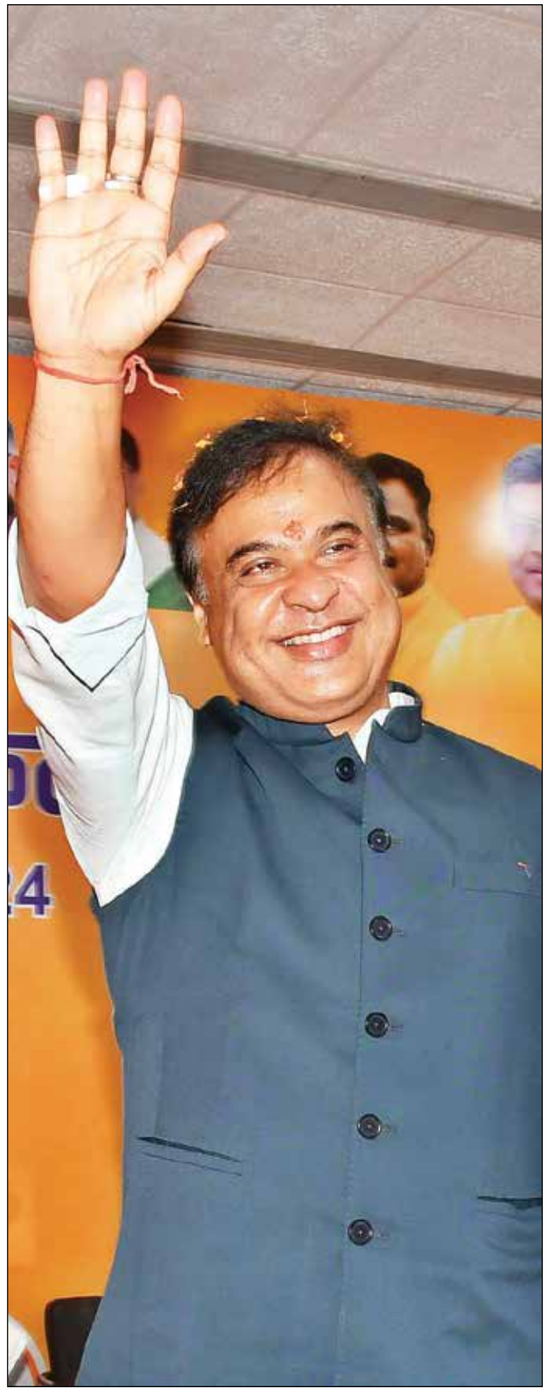
बीते पांच वर्षों में सरमा सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए 1.65 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान कीं और प्रशासन के डिजिटलीकरण को तेज़ किया, जिससे राज्य की छवि में उल्लेखनीय बदलाव आया। महिला सशक्तिकरण के लिए 'अरुणोदय' जैसी योजनाओं को इस बदलाव के महत्वपूर्ण स्तंभों में गिना जाता है। पिछले एक वर्ष में शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा निवेश हुआ — 2025-26 के दौरान मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी और मुख्यमंत्री निजुत बाबू सोनी जैसी दो प्रमुख छात्र सहायता योजनाओं के तहत 176 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए, ताकि वित्तीय बाधाएं किसी भी योग्य छात्र को उच्च शिक्षा से वंचित न करें।

महत्वपूर्ण पहलें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का ध्यान असम की बढ़ती कार्यशक्ति के लिए नए अवसर पैदा करने, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने पर केंद्रित है।

इससे आगे बढ़ते हुए सरमा ने घोषणा की कि राज्य 2026 से 2031 के बीच बुनियादी ढांचे पर 1.50 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा — यह असम के इतिहास की सबसे बड़ी अवसंरचना निवेश योजनाओं में से एक है। इसी क्रम में उद्योग जगत के नेताओं से सीधा आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने निवेशकों को नीतिगत सहयोग, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता का भरोसा दिलाया, और असम को अपना "घर" बनाने का न्योता दिया — यह दिखाता है कि सरमा स्वयं निवेश आकर्षण अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम

स्वास्थ्य के मोर्चे पर सरमा सरकार की सबसे चर्चित पहल असम कैंसर केयर फाउंडेशन के अंतर्गत राज्यभर में स्थापित किए जा रहे अत्याधुनिक कैंसर संस्थान रहे हैं। कुल सत्रह प्रस्तावित कैंसर संस्थानों की यह श्रृंखला दूरदराज के क्षेत्रों तक विश्वस्तरीय कैंसर



उपचार सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है, और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। यह पहल दर्शाती है कि सरमा सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना को केवल शहरी केंद्रों तक सीमित न रखकर राज्य के हर कोने तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जमीनी कनेक्टिविटी और स्थानीय विकास

सरमा के नेतृत्व में विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। हाल ही में जोरहाट जिले में मुख्यमंत्री ने 122 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें जिला आयुक्त का नया एकीकृत कार्यालय भवन, स्कूल और विश्वविद्यालय की नई इमारतें तथा एक महत्वपूर्ण रेलवे फ्लाईओवर शामिल हैं — यह वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जोरहाट को समर्पित चौथा प्रमुख फ्लाईओवर है। मुख्यमंत्री ने इसे क्षेत्र में परिवहन और कनेक्टिविटी विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इसी अवसर पर आयोजित जिला आयुक्तों के सम्मेलन में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई — यह दिखाता है कि सरमा जिला-स्तरीय प्रशासन को भी उतनी ही बारीकी से मॉनिटर करते हैं जितना राज्य-स्तरीय नीतियों को।

इसके अलावा राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वनियोजन योजना जैसी पहलों के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है, जिसमें दो लाख से पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और लगभग 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

एक निर्णायक नेतृत्व की कहानी

हिमंता बिस्वा सरमा की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के प्रति बरसों से चली आ रही उपेक्षा की धारणा को चुनौती दी है। सेमीकंडक्टर संयंत्र से लेकर कैंसर अस्पतालों तक, और डिजिटल शासन से लेकर जिला-स्तरीय फ्लाईओवरों तक — सरमा ने यह साबित किया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और निरंतर क्रियान्वयन से किसी भी राज्य की तस्वीर बदली जा सकती है। पिछला एक वर्ष इस यात्रा का सबसे निर्णायक चरण रहा है, जिसमें लगातार तीसरी बार जनादेश, सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत और लाखों करोड़ रुपये के निवेश की घोषणाएं शामिल हैं। यह विकास गाथा दिखाती है कि हिमंता बिस्वा सरमा असम को 'चाय के बागानों की भूमि' से 'तकनीक और निवेश के केंद्र' में बदलने के अपने संकल्प पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।



4

जब 2022 में भगवंत सिंह मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री की शपथ ली, तब राज्य कई दशकों की चुनौतियों — नशे की मार, बेरोजगारी और औद्योगिक ठहराव — से जूझ रहा था। लेकिन बीते चार वर्षों में मान के नेतृत्व में पंजाब ने अपनी दिशा बदली है। "काम की राजनीति" के अपने नारे को साकार करते हुए मुख्यमंत्री मान ने चार वर्ष पूरे होने पर चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा को नकार कर आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया था, और उस भरोसे को उन्होंने टूटने नहीं दिया। यह आत्मविश्वास आंकड़ों में भी झलकता है — रोजगार, निवेश और सुशासन के तीन मोर्चों पर पंजाब ने बड़ी छलांग लगाई है।

पंजाब को नई दिशा देने वाले जननायक

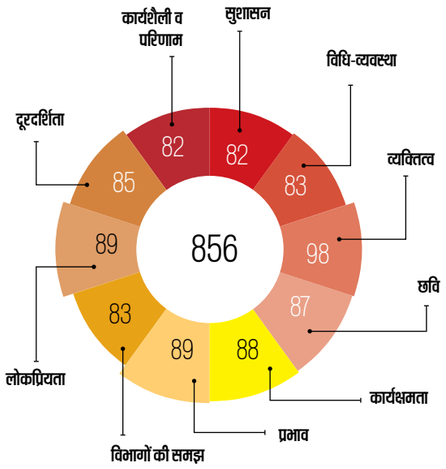
भगवंत मान

एक नए पंजाब की नींव



रोजगार की नई गारंट

भगवंत मान सरकार की सबसे बड़ी पहचान बनी है — बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के पारदर्शी नौकरियां। अप्रैल 2022 से अगस्त 2026 तक सरकार 70,840 से अधिक सरकारी नौकरियां दे चुकी है। इसी क्रम में हाल ही में 27 अगस्त 2026 को 1,746 पुलिस जवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए — यह उन 1,746 परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया, और सरकार ने इसे योग्यता और मेहनत के आधार पर रोजगार देने के अपने मॉडल की मिसाल बताया। पंजाब विधानसभा ने भी हाल ही में सरकार की इस उपलब्धि को सराहते हुए 68,228 सरकारी नौकरियों को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राज्य के अभूतपूर्व औद्योगिक और निजी क्षेत्र विकास को स्वीकार किया गया।



निवेश के मोर्चे पर ऐतिहासिक सफलता

पंजाब को लंबे समय तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जाता रहा है, लेकिन मान सरकार ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। पंजाब विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार 16 मार्च 2022 से 31 जुलाई 2026 के बीच राज्य को 1,83,837 करोड़ रुपये के 9,899 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 6,16,436 रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत टेक्स 2026 के मंच से मुख्यमंत्री मान ने स्वयं यह आंकड़ा साझा करते हुए बताया कि पिछले चार वर्षों में पंजाब ने दो लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे पांच लाख नए रोजगार पैदा हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राज्य में किसी भी अधिकारी द्वारा उद्योगों को तंग-परेशान नहीं किया जाता — यह प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

पिछले एक वर्ष की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि रही 'प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन-2026', जिसका मोहाली में तीन दिवसीय भव्य आयोजन हुआ। इस सम्मेलन के पहले ही दिन पंजाब को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले, जिसमें दिग्गज उद्योगपतियों ने राज्य में अपना कारोबार और बढ़ाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री मान ने इस अवसर पर राज्य के औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा देने की बात करते हुए इसे बड़े गर्व और संतोष का विषय बताया। इसी सम्मेलन श्रृंखला के तहत मुंबई में आयोजित निवेश रोड शो में भी पंजाब सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों को बड़े उद्यमों में बदलने तथा विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और उभरते क्षेत्रों में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने पर विशेष जोर दिया।

नई औद्योगिक नीति: निवेशकों के लिए खुला द्वार

निवेश के इस उभार को संस्थागत रूप देने के लिए मान सरकार ने 'पंजाब औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति–2026' की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मान ने इसे देश की सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नीति बताया, जिसके तहत निवेशक अपने व्यापार मॉडल के अनुसार रियायतों का लाभ उठा सकेंगे। छोटे उद्योगों को समर्थन देने के लिए रोजगार सृजन सब्सिडी की पात्रता सीमा घटाकर 25 करोड़ रुपये के निवेश और 50 श्रमिकों तक कर दी गई है — यह दर्शाता है कि सरकार की नीतियां केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं, बल्कि छोटे और मझोले उद्यमों को भी सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं।



एक साझा विजन: सरकार और उद्योग की भागीदारी

मुख्यमंत्री मान का मानना है कि औद्योगिक विकास तभी संभव है जब सरकार और उद्योग एक साथ मिलकर कार्य करें। भारत टेक्स 2026 में उन्होंने स्पष्ट किया कि निवेशक और उद्यमी पंजाब के औद्योगिक भविष्य के मुख्य स्तंभ हैं, और राज्य पारदर्शी, उद्योग-अनुकूल दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। यही सोच पंजाब को निवेश के मानचित्र पर लगातार ऊपर ले जा रही है।

टेक्सटाइल क्षेत्र में भी पंजाब ने बड़ी पहचान बनाई है। भारत टेक्स 2026 के मंच से मुख्यमंत्री मान ने पंजाब को टेक्सटाइल निवेश के लिए देश का सबसे पसंदीदा गंतव्य बताते हुए कहा कि राज्य में मौजूद एकीकृत टेक्सटाइल वैल्यू चेन के जरिए अब यह केवल उत्पादन का नहीं, बल्कि नवाचार और वैश्विक निर्यात का केंद्र बन रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि उचित बिजली दरें, भूमि संबंधी सुविधाएं और निवेशक-अनुकूल वातावरण पंजाब को व्यापार करने में आसानी के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल करा रहे हैं।

नशे के खिलाफ निर्णायक जंग

भगवंत मान सरकार की सबसे साहसिक पहलों में से एक रही है नशे के खिलाफ छेड़ी गई 'युद्ध नशियां विरुद्ध' मुहिम। इस अभियान के तहत राज्यभर में नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बठिंडा की कुख्यात धोबियाना बस्ती में नशा तस्करों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकानों को ध्वस्त किया गया — पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई राज्य सरकार की नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। यह अभियान दिखाता है कि मान सरकार पंजाब को नशा मुक्त बनाने के अपने संकल्प पर गंभीरता से आगे बढ़ रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को नशे के विनाशकारी प्रभावों से बचाया जा सके।

शिक्षा में नवाचार की दिशा

शिक्षा क्षेत्र में भी मान सरकार नए प्रयोगों के लिए जानी जा रही है। हाल ही में



राज्य के 25 स्कूलों में एआई-आधारित करियर गाइडेंस पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से भविष्य के करियर विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन देने की दिशा में एक अग्रणी कदम है। यह पहल दिखाती है कि सरकार पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को तकनीकी नवाचार से जोड़कर विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने पर ध्यान दे रही है।

बदलाव की एक सतत यात्रा

भगवंत मान का नेतृत्व दिखाता है कि किसी राज्य की पुरानी छवि को बदलने के लिए दृढ़ नीति, पारदर्शी प्रशासन और निरंतर क्रियान्वयन की जरूरत होती है। रोजगार में पारदर्शिता, निवेश में रिकॉर्ड वृद्धि, नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शिक्षा में नवाचार — इन चार स्तंभों पर खड़ा पंजाब का नया मॉडल यह संकेत देता है कि राज्य अपनी पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़कर एक नई आर्थिक और सामाजिक पहचान गढ़ रहा है। पिछला एक वर्ष इस यात्रा का सबसे सक्रिय चरण रहा है, जिसमें प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन, नई औद्योगिक नीति और नशा-विरोधी अभियान की तेज़ रफ्तार शामिल है — यह सब मिलकर भगवंत मान की उस "काम की राजनीति" को साकार करता है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी सरकार खड़ी की थी।



5

झारखंड, जो अपनी खनिज संपदा और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिख रहा है। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, हेमंत सोरेन ने राज्य की सबसे कमजोर आबादी—महिलाओं, आदिवासियों, किसानों और युवाओं—को केंद्र में रखकर एक ऐसा शासन मॉडल विकसित किया है, जिसे "झारखंड मॉडल" के रूप में पहचाना जाने लगा है।

झारखंड के विकास और जनकल्याण के प्रतीक

हेमंत सोरेन

आदिवासी अस्मिता और जनकल्याण का संगम



राष्ट्रीय मंच पर झारखंड की आवाज़

हेमंत सोरेन ने झारखंड के हितों को राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती से उठाया है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की तैयारी में राज्य सरकार ने खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों के लिए विशेष सहायता और आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास जैसे मुद्दे प्रमुखता से रखने की तैयारी की, जो यह दर्शाता है कि हेमंत सोरेन झारखंड के संसाधनों पर राज्य के वाजिब हक की पैरवी करने में कभी पीछे नहीं रहते।



अबुआ दिशोम बजट: जनकल्याण को समर्पित वित्तीय दृष्टि

हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपये का आम बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष के 1.45 लाख करोड़ रुपये के बजट से बड़ा है। इस बजट को "अबुआ दिशोम बजट" नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य राज्य के समग्र विकास, सामाजिक कल्याण और आर्थिक बदलाव को गति देना है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने आउटकम बजट, जेंडर बजट और चाइल्ड बजट भी प्रस्तुत किया, जो यह दिखाता है कि हेमंत सोरेन सरकार खर्च के परिणामों के प्रति जवाबदेह होने का प्रयास कर रही है।

बजट में सामाजिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली—कुल बजट का सर्वाधिक 16.75 प्रतिशत हिस्सा समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया, जो स्पष्ट करता है कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता, विशेषकर वंचित वर्गों तक सीधा लाभ पहुंचाना है।

मईयां सम्मान योजना: महिला सशक्तिकरण की मिसाल

हेमंत सोरेन की सबसे लोकप्रिय और परिवर्तनकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना अग्रणी है। झारखंड की करीब 60 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं, जिससे यह देश की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में शुमार हो चुकी है। इस योजना का असर केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहा—रांची जिले में ही मई 2025 तक 6,844 लाभार्थी महिलाओं के बीच 2,13,409 चूजों का वितरण किया गया, साथ ही 1,347 लाभुकों के बीच 18,819 बत्तख और 1,522 लाभुकों के बीच 5,253 बकरियों का वितरण किया गया, जिससे महिलाएं अंडा उत्पादन और पशुपालन के जरिए स्वावलंबी बन रही हैं। 2026-27 के बजट में इस योजना की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, पोषण तथा सर्वांगीण विकास के लिए 22,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

अबुआ आवास योजना: हर गरीब को पक्की छत

हेमंत सोरेन सरकार ने बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की, जिसे 15 अगस्त 2023 को स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरंभ किया था और



ग्रामीण विकास और ऊर्जा: बुनियादी ढांचे की मजबूती

बजट में ग्रामीण विकास विभाग को 12,346.90 करोड़ रुपये और ऊर्जा विभाग को 11,197.89 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो गांवों की बुनियादी सुविधाओं और बिजली आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मानसून सत्र में सरकार ने करीब 6,500 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट भी पेश किया, जिसमें विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किया गया—यह दिखाता है कि सरकार ग्रामीण रोजगार सृजन के प्रति निरंतर सक्रिय है।

इसकी पहली किश्त 23 जनवरी 2024 को वितरित की गई। इस योजना की पात्रता मानदंड में झारखंड का मूल निवासी होना, मिट्टी के घरों में रहना, बेघर होना, कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित होना या प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होना शामिल है, जो दर्शाता है कि यह योजना समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों तक पहुंचने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। लाभार्थियों को चार किस्तों में पहली किस्त में 30,000 रुपये, दूसरी में 50,000 रुपये, तीसरी में एक लाख रुपये और अंतिम किस्त में 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है, ताकि हर परिवार को पक्की छत नसीब हो सके।

शिक्षा: आदिवासी युवाओं के लिए वैश्विक अवसर

हेमंत सोरेन सरकार ने शिक्षा को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा माध्यम बनाया है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को लंदन और यूके के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाती है, और हाल ही में इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इसी तरह गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को बिना किसी गारंटी के 15 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आर्थिक तंगी अब झारखंड के प्रतिभाशाली छात्रों के सपनों में बाधा नहीं बनती।

2026-27 के बजट में शिक्षा को और मजबूती दी गई—प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। चतरा में एक नया अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा हुई, साथ



ही धनबाद में दो और पलामू, लातेहार व गढ़वा में एक-एक, कुल पांच झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय बनाए जाने की योजना है, और 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। संस्कृति और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में सेंटर ऑफ आर्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के संचालन को मंजूरी दी गई, जो हेमंत सोरेन की उस सोच को दर्शाता है कि विकास केवल आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक भी होना चाहिए।

स्वास्थ्य और रोजगार: गांव-गांव तक सेवा

हेमंत सोरेन सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर बहाली अभियान चलाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 262 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और इस अवसर पर उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य कर रही है। सरकार अब मेडिकल ऑफिसर से आगे बढ़कर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति कर रही है, जो सीधे गांव-गांव जाकर जनता को सेवा देंगे, और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 56 फूड सेफ्टी ऑफिसरों की भी नियुक्ति की जा रही है।

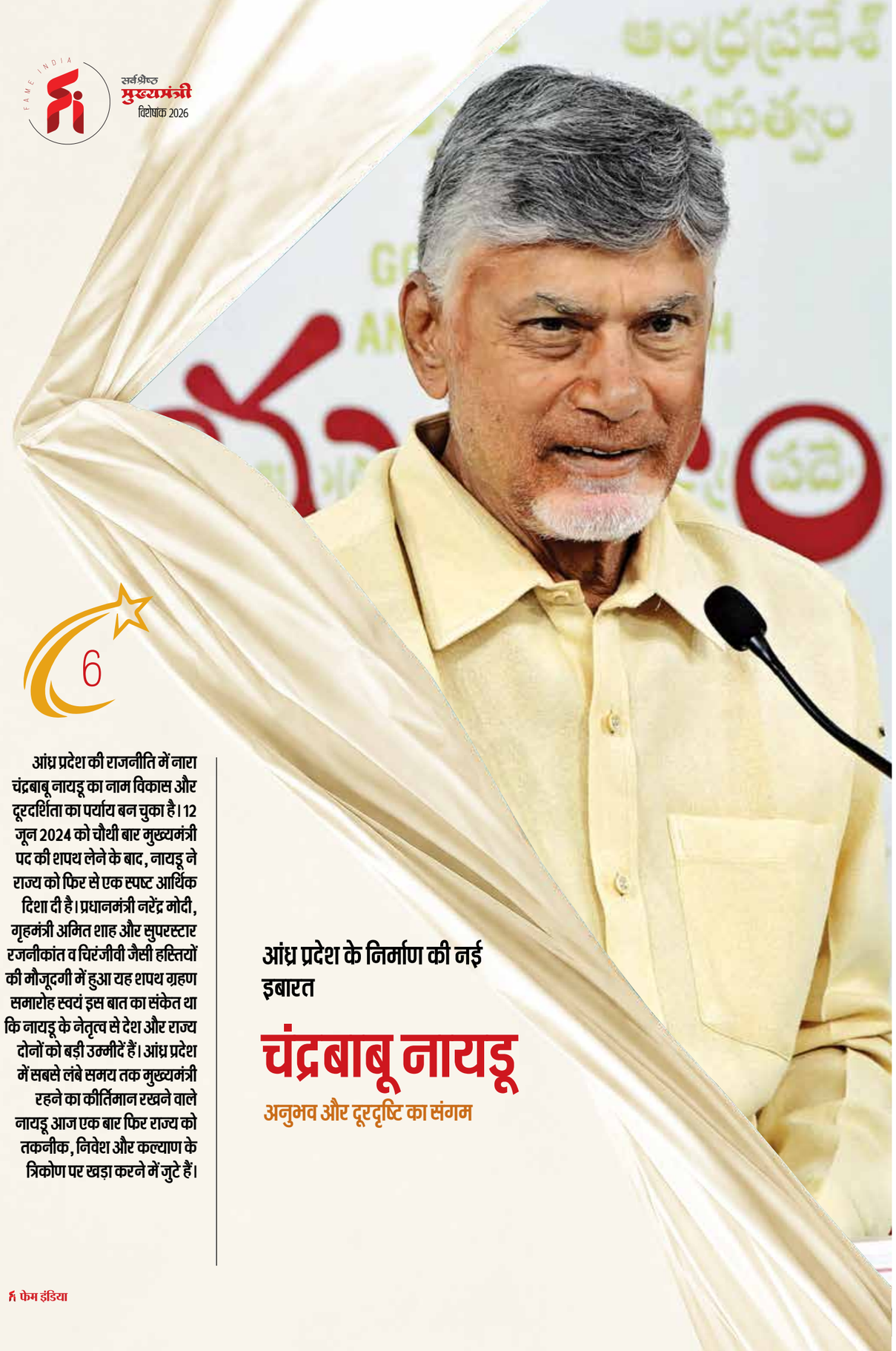
प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए भी हेमंत सोरेन व्यक्तिगत रूप से सक्रिय रहे हैं। जून 2026 में उन्होंने श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए देश के सभी राज्यों में श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया, और तीन महीने के भीतर सभी प्रवासी मजदूरों का डाटा श्रमिक पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा—यह दर्शाता है कि झारखंड से बाहर काम करने वाले श्रमिक भी सरकार की प्राथमिकता से बाहर नहीं हैं।

सामाजिक सुरक्षा: बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों का संबल

हेमंत सोरेन सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,517 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता, विधवा और अपंग पेंशन योजनाओं के लिए 1,463 करोड़ रुपये से अधिक की राशि तय की गई, ताकि जरूरतमंद बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।

जन-कल्याण की निरंतर यात्र

हेमंत सोरेन का नेतृत्व झारखंड के लिए एक ऐसे शासन मॉडल का प्रतीक बन चुका है। "झारखंड की मईया" को समर्पित यह बजट और इससे जुड़ी योजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की एक नई गाथा लिख रहा है।



6

आंध्र प्रदेश की राजनीति में नारा चंद्रबाबू नायडू का नाम विकास और दूरदर्शिता का पर्याय बन चुका है। 12 जून 2024 को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, नायडू ने राज्य को फिर से एक स्पष्ट आर्थिक दिशा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सुपरस्टार रजनीकांत व चिरंजीवी जैसी हस्तियों की मौजूदगी में हुआ यह शपथ ग्रहण समारोह स्वयं इस बात का संकेत था कि नायडू के नेतृत्व से देश और राज्य दोनों को बड़ी उम्मीदें हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान रखने वाले नायडू आज एक बार फिर राज्य को तकनीक, निवेश और कल्याण के त्रिकोण पर खड़ा करने में जुटे हैं।

आंध्र प्रदेश के निर्माण की नई इबारत

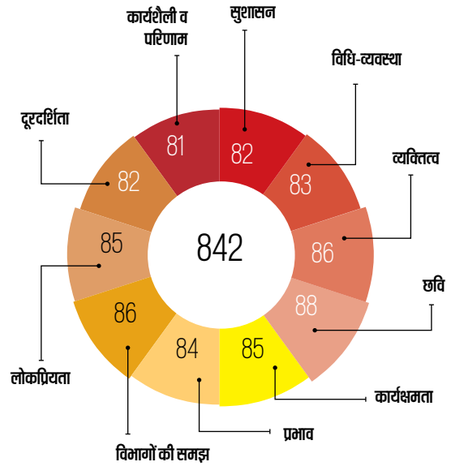
चंद्रबाबू नायडू

अनुभव और दूरदृष्टि का संगम



सुधारों की नई पीढ़ी: निवेशकों के लिए सहज माहौल

नायडू सरकार ने निवेश को केवल आकर्षित करने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सुगम बनाने के लिए ठोस नीतिगत सुधार भी किए। अगस्त 2026 में मंत्रिमंडल ने पीपीपी नीति-2026 और आंध्र प्रदेश ओम्निबस (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) अधिनियम-2026 के मसौदे को मंजूरी दी, जिसमें निवेश, औद्योगिक मंजूरी, सड़क सुरक्षा, क्वांटम अवसंरचना और जलीय कृषि से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नायडू ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निवेश नीतियों को लागू करने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी निवेशकों को समान अवसर मिलने चाहिए—यह उनकी शासन शैली में पारदर्शिता और निष्पक्षता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



अमरावती: विश्वस्तरीय राजधानी का सपना साकार होता

नायडू की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा रही है अमरावती को एक विश्वस्तरीय राजधानी के रूप में विकसित करना। उन्होंने अमरावती को आंध्र प्रदेश के प्रमुख आर्थिक केंद्र और विकास इंजन के रूप में विकसित करने की दिशा में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक समर्पित वित्तीय जिला स्थापित करने तथा वहां जल, बिजली और गैस आपूर्ति की समुचित व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। "मिशन सिंगापुर" के तहत नायडू स्वयं सिंगापुर गए, जहां उन्होंने भारत के उच्चायुक्त और स्टार्टअप वेंचर कैपिटल निवेशकों के साथ बैठकें कीं तथा संयुक्त राष्ट्र-हैबिटैट की कार्यकारी निदेशक से भी मुलाकात की, ताकि अमरावती को सिंगापुर जैसी सुधार व्यवस्था पर विकसित किया जा सके।

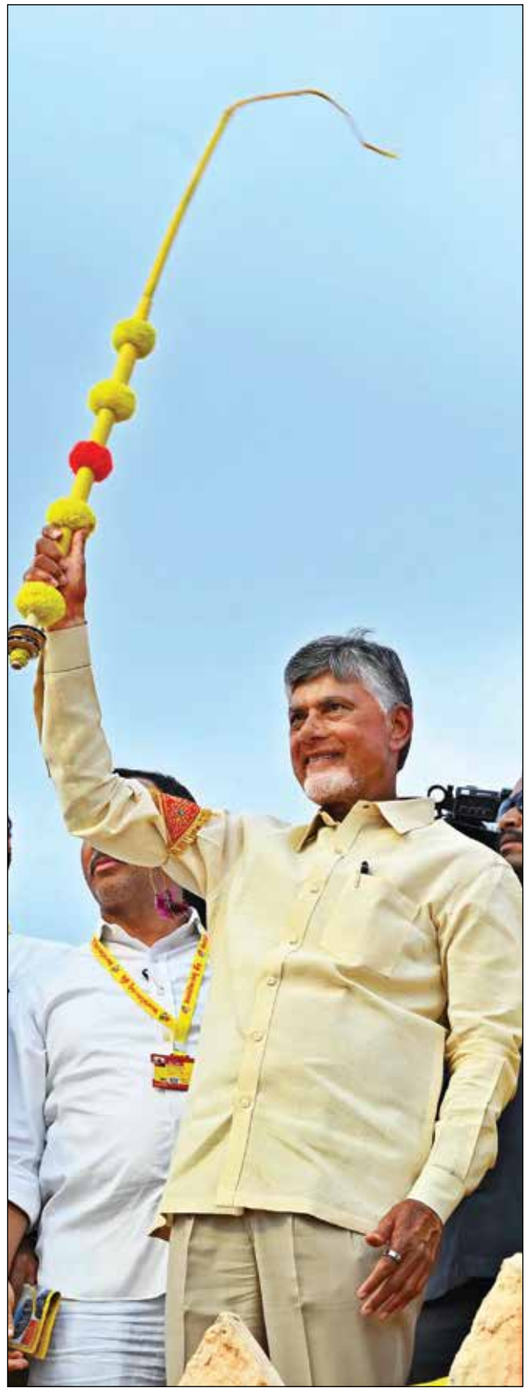
अमरावती में क्वांटम वैली ट्विन टावर्स के निर्माण के लिए 1,002.49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा अमरावती संगमम परियोजना को भी मंजूरी दी गई। रामायपट्टनम बंदरगाह और अमरावती में निर्माण कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड को भी मंजूरी दी गई।

निवेश की नई लहर: गूगल का 15 अरब डॉलर का ऐतिहासिक निवेश

नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश निवेश के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो चुका है। रायसीना डायलॉग 2026 में नायडू ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश में गूगल पहली बार 15 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है, जिसके तहत एक गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर और एआई से जुड़ी परियोजनाएं स्थापित होंगी।

निवेश आकर्षित करने की यह रफ्तार लगातार बनी हुई है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) की बैठकों में नायडू की अध्यक्षता में एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए—अप्रैल 2026 में नवीकरणीय ऊर्जा, उद्योग, आईटी, पर्यटन और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों में 39,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनसे 1.11 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई, और इसी दौरान अमरावती के प्रस्तावित 'क्वांटम वैली' में तीन कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिली। जनवरी 2026 में 19,391 करोड़ रुपये के निवेश से 11,753 नौकरियां पैदा करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें नायडू ने फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में आंध्र प्रदेश को वैश्विक चैंपियन बनाने पर जोर दिया। हाल ही में सितंबर 2026 में 22,177.84 करोड़ रुपये के निवेश वाली 28 औद्योगिक





अनुभवी नेतृत्व, नई ऊर्जा

चंद्रबाबू नायडू का चौथा कार्यकाल यह साबित करता है कि दशकों का प्रशासनिक अनुभव जब स्पष्ट दृष्टि और आधुनिक तकनीकी सोच से जुड़ता है, तो किसी भी राज्य की तस्वीर बदली जा सकती है। उनकी यह यात्रा दिखाती है कि आंध्र प्रदेश केवल एक कृषि प्रधान राज्य नहीं, बल्कि क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और वैश्विक निवेश के मानचित्र पर अपनी जगह बनाने वाला एक भविष्योन्मुखी राज्य बनने की दिशा में मजबूती से अग्रसर है।

परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनसे करीब 20,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

सुपर सिक्स: चुनावी वादों से जमीनी हकीकत तक

नायडू सरकार की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि रही है 2024 चुनाव से पहले किए गए 'सुपर सिक्स' वादों को व्यवस्थित रूप से जमीन पर उतारना। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश 3.22 लाख करोड़ रुपये के बजट में कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र में रखा गया। इसके तहत हर स्कूल जाने वाले बच्चे को 'तल्लिकी वंदनम' के अंतर्गत प्रति वर्ष 15,000 रुपये, हर घर को 'दीपम-2' योजना के तहत तीन मुफ्त गैस सिलेंडर, और हर किसान को 'अन्नदाता सुखीभवा' योजना के अंतर्गत 20,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया।

नायडू ने इन वादों को महज घोषणा तक सीमित नहीं रखा। सरकार ने पहली वर्षगांठ पर तल्लिकी वंदनम योजना का शुभारंभ करते हुए बताया कि गठबंधन सरकार 67 लाख छात्रों को इस योजना के तहत वित्तीय लाभ दे रही है, जो पिछली सरकार की तुलना में 24.65 लाख अधिक छात्र हैं। इस योजना पर स्कूल विकास के लिए 1,346 करोड़ रुपये सहित कुल 10,091 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की गई। नायडू ने स्वयं कहा कि परिवार में चाहे कितने भी बच्चे हों, हर छात्र को इस योजना का लाभ मिलेगा—यह उनकी उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वादे केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहने चाहिए।

अन्नदाता सुखीभवा-पीएम किसान योजना का शुभारंभ भी नायडू ने स्वयं प्रकाशम जिले में किया, जहां राज्य के 46,85,838 किसानों को 3,175 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इसमें 45.69 लाख भूमिधारक किसान परिवारों के साथ-साथ वनाधिकार कानून के तहत खेती करने वाले 1.16 लाख से अधिक आरओएफआर किसान परिवार भी शामिल किए गए, जो दिखाता है कि योजना का दायरा केवल भूस्वामी किसानों तक सीमित नहीं, बल्कि वनवासी कृषकों तक भी फैला हुआ है।

औद्योगिक विविधीकरण: पारंपरिक से भविष्योन्मुखी क्षेत्रों तक

नायडू की दूरदृष्टि केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में गूगल केंद्र लाने के लिए मंत्री नारा लोकेश के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य को क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने का विजन साझा किया। साथ ही उन्होंने तिरुपति क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने पर जोर दिया, ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके और फूड प्रोसेसिंग उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला वैश्विक बाजार तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के समुद्र तट के साथ बंदरगाहों से जुड़ा व्यापक बुनियादी ढांचा तंत्र विकसित करने का निर्देश भी दिया, जिससे तटीय आंध्र प्रदेश की आर्थिक क्षमता का पूरा उपयोग हो सके।

राष्ट्रीय राजनीति में सम्मानित आवाज़

नायडू की राजनीतिक कुशलता और अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक मान्यता मिली है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भरपूर प्रशंसा करते हुए उन्हें ऊर्जावान, दूरदर्शी और वैश्विक स्तर पर सम्मानित नेता बताया, तथा विश्वास जताया कि मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यह भी दर्शाता है कि नायडू केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसका सीधा लाभ आंध्र प्रदेश को केंद्रीय योजनाओं और निवेश के रूप में मिल रहा है।

INDIA FUTURE FUELS & ENERGY SUMMIT 2026

POWERING VIKSIT BHARAT

ASSOCIATE PARTNER

iba Indian Biogas Association

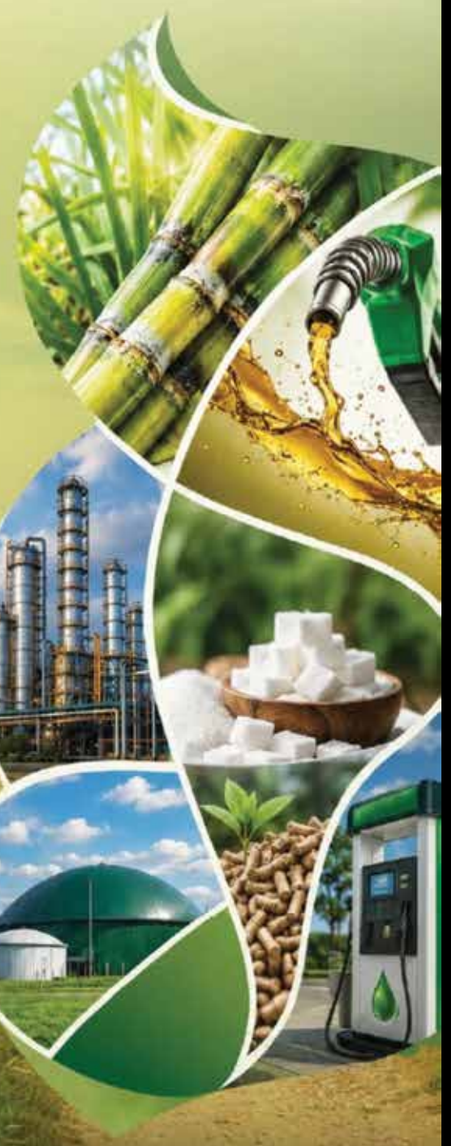
INDIA FUTURE FUELS & ENERGY SUMMIT 2026

Accelerating The Transition To Clean, Secure & Future-Ready Energy

SCAN FOR REGISTRATION!

27th November, 2026

Le-Meridien Windsor Place
Connaught Place,
New Delhi - 110001



RNI No. DELHIN/2012/48773 विशेषांक 2026 वर्ष 14, अंक 10

फेम इंडिया

सोच बदलें, समाज बदलेगा



अविनाश रंजन झा

कॉरपोरेट दुनिया से राजनीति के मैदान तक





भारतीय राजनीति में कुछ लोग अपनी पहचान पद और राजनीतिक विरासत से बनाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने संघर्ष, संगठनात्मक क्षमता, विचारों और सामाजिक प्रतिबद्धता के दम पर अलग स्थान हासिल करते हैं। अविनाश रंजन झा ऐसे ही व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा को मेहनत, अनुभव और निरंतर सक्रियता के माध्यम से आगे बढ़ाया है। लगभग 18 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में रहते हुए उन्होंने संगठन, चुनावी रणनीति, जनसंपर्क और नीतिगत चिंतन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई है।

अविनाश रंजन झा का गहरा जुड़ाव बिहार से रहा है। उनका पैतृक स्थान मधुबनी है, लेकिन उनका जन्म तब हुआ था जब परिवार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रह रहा था। उनका पालन-पोषण बिहार में हुआ। वर्तमान में पटना में रहते हुए वे बिहार की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों से निरंतर जुड़े हुए हैं।

कॉरपोरेट जीवन से राजनीति तक

अविनाश रंजन झा की राजनीतिक यात्रा छात्र जीवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शुरू हुई। हालांकि, वर्ष 2008 में आई कोसी की विनाशकारी बाढ़ उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। बाढ़ के कारण हजारों परिवारों को विस्थापन, आर्थिक संकट और मानवीय पीड़ा का सामना करना पड़ा। इस त्रासदी ने उन्हें समाज और सार्वजनिक जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने महसूस किया कि व्यक्तिगत करियर की सफलता से आगे बढ़कर समाज के लिए काम करना भी आवश्यक है। इसी सोच के साथ उन्होंने कॉरपोरेट जीवन को पीछे छोड़कर सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता का रास्ता चुना। यह निर्णय उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ।

संगठनात्मक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका

वर्ष 2010 से 2022 तक उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के राज्य संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं। प्रदेश सचिव और बाद में प्रदेश महासचिव के रूप में उन्होंने कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेतृत्व और आम जनता के बीच काम किया।

उनकी राजनीतिक कार्यशैली की विशेषता यह रही कि उन्होंने संगठन को केवल पद या कार्यालय के रूप में नहीं देखा। उनके लिए संगठन का अर्थ कार्यकर्ताओं से संवाद, जनता के बीच सक्रियता और स्थानीय समस्याओं की समझ है।

वर्ष 2022 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनकी सक्रिय भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उन्हें विधानसभा समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विधानसभा



पर्यवेक्षक बनाए गए।

गुजरात में जिस विधानसभा सीट की जिम्मेदारी उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में मिली, वहां कांग्रेस की जीत उनकी संगठनात्मक क्षमता और चुनावी रणनीति की उल्लेखनीय उपलब्धि रही।

चुनावी रणनीति और जमीनी राजनीति

अविनाश रंजन झा की राजनीति का एक महत्वपूर्ण आधार जमीनी संपर्क है। उनका मानना है कि राजनीति केवल भाषणों, सोशल मीडिया और बड़े आयोजनों तक सीमित नहीं हो सकती। वास्तविक राजनीतिक प्रभाव जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने और उनके विश्वास को हासिल करने से बनता है।



उनकी चुनावी कार्यशैली में घर-घर संपर्क, छोटे समूहों में संवाद, बूथ स्तर पर तैयारी, स्थानीय नेतृत्व के साथ समन्वय और मतदाताओं की प्रतिक्रिया को विशेष महत्व दिया जाता है।

वे चुनावी रणनीति में आंकड़ों और जमीनी अनुभव, दोनों को आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार सर्वेक्षण और राजनीतिक आंकड़े किसी क्षेत्र की परिस्थितियों को समझने में मदद करते हैं, लेकिन वास्तविक कारणों को जानने के लिए जनता के बीच जाना जरूरी है। यही कारण है कि वे आंकड़ों के विश्लेषण के साथ प्रत्यक्ष जनसंपर्क को भी समान महत्व देते हैं।

लेखन और बिहार के विकास की सोच

राजनीतिक गतिविधियों के अतिरिक्त अविनाश रंजन झा की रुचि लेखन और नीतिगत चिंतन में भी रही है। उन्होंने बिहार के विकास, पुनर्निर्माण, प्रशासनिक सुधार, आधुनिक आधारभूत संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था, रोजगार और युवाओं के अवसरों जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।

वे बिहार को केवल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के नजरिये से नहीं देखते, बल्कि आने वाले दशकों की आर्थिक और तकनीकी संभावनाओं के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि राज्य के विकास के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशासन, मजबूत आधारभूत ढांचे और रोजगार के नए अवसरों पर ध्यान देना आवश्यक है।

ज्योतिष और भविष्य को समझने की रुचि

उनके व्यक्तित्व का एक विशिष्ट पक्ष ज्योतिष का अध्ययन भी है। वे ज्योतिष में रुचि रखते हैं और इसे घटनाओं तथा संभावनाओं को एक अलग दृष्टिकोण से समझने का माध्यम मानते हैं।

उनके कुछ राजनीतिक आकलनों के उदाहरण भी परिचितों के बीच चर्चा में रहे हैं। एक राजनीतिक नेता को उन्होंने तत्काल मंत्रिमंडल में शामिल होने की अपेक्षा कुछ समय प्रतीक्षा करने की सलाह दी थी। बाद में उस नेता को उच्च स्तर की महत्वपूर्ण कैबिनेट जिम्मेदारी मिली और एक से अधिक मंत्रालयों का दायित्व भी प्राप्त हुआ।

हिमालय और कैलाश के प्रति भी उनका विशेष दृष्टिकोण रहा है। वे इन्हें भारतीय सभ्यता और आध्यात्मिक चेतना के महत्वपूर्ण केंद्र मानते हैं। उनका विचार है कि प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ और असंतुलित विकास के परिणाम समाज के लिए विनाशकारी हो सकते हैं।





तकनीक और राष्ट्रीय संप्रभुता

अविनाश रंजन झा की वैचारिक सक्रियता तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों तक भी पहुंचती है। अपनी पुस्तक में उन्होंने सरकारी व्यवस्थाओं में विदेशी जासूसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से जुड़े संभावित जोखिमों पर चिंता व्यक्त की थी।

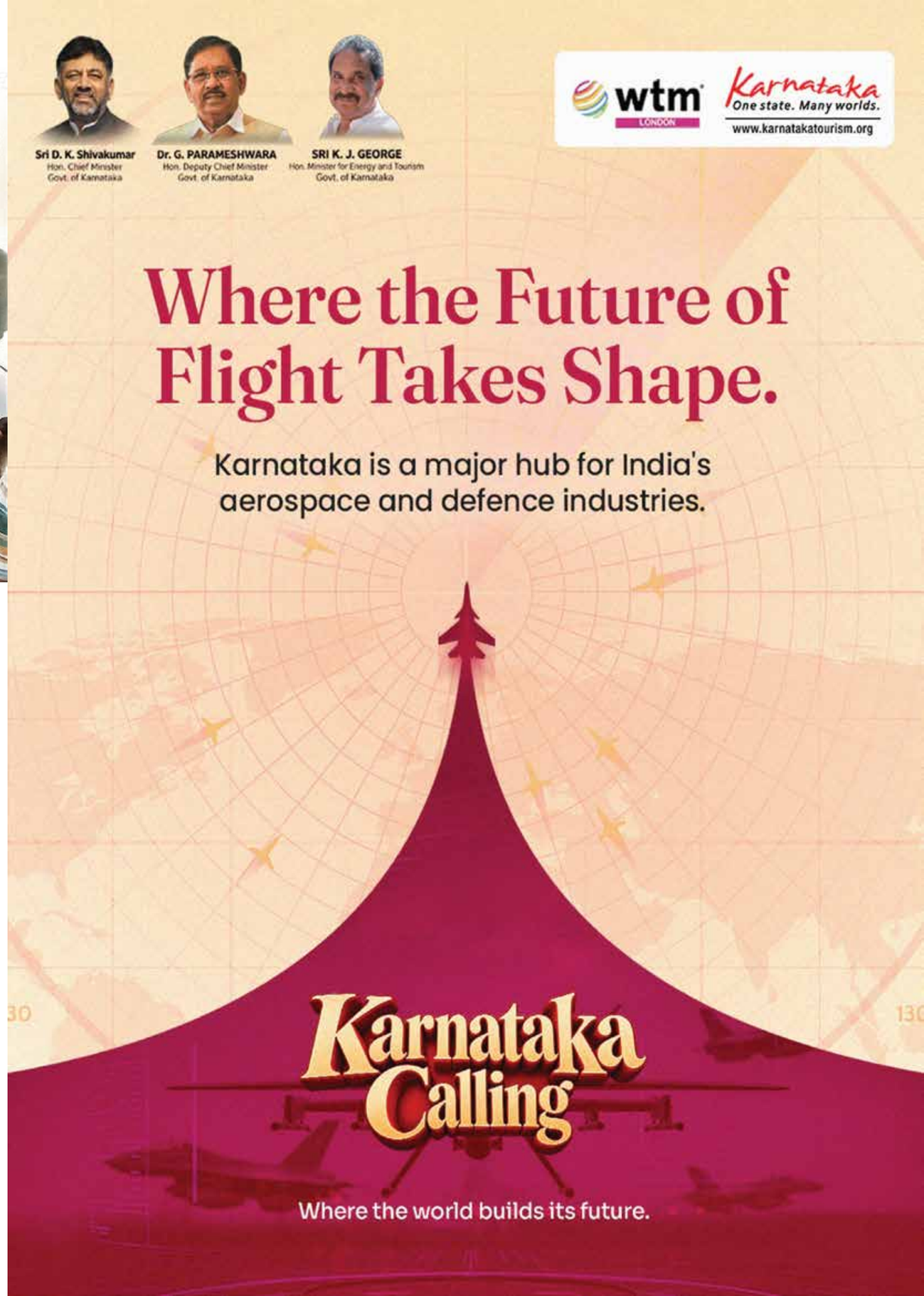
उनका मानना है कि डिजिटल तकनीक आधुनिक शासन का महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन संवेदनशील सरकारी व्यवस्थाओं में विदेशी तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता के लिए चुनौती बन सकती है।

पद से आगे राजनीतिक पहचान

लगभग दो दशकों की राजनीतिक सक्रियता के बावजूद उन्हें अब तक विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा को पद प्राप्ति तक सीमित नहीं रखा। संगठन में काम करना, कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहना, चुनावी रणनीति बनाना और सामाजिक मुद्दों पर लिखना उनके लिए राजनीतिक योगदान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

अविनाश रंजन झा की अब तक की यात्रा संघर्ष, संगठनात्मक अनुभव, रणनीतिक सोच और भविष्य के प्रति उनकी दृष्टि का परिचय देती है। कॉरपोरेट जीवन से सार्वजनिक जीवन तक का सफर, कोसी की बाढ़ से मिली प्रेरणा, विभिन्न संगठनों में जिम्मेदारियां और राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी अनुभव उनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण आयाम हैं।

उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि राजनीति में पहचान केवल पद से नहीं, बल्कि वर्षों के काम, विचार और प्रतिबद्धता से भी बनाई जा सकती है। आने वाले समय में उनका अनुभव किस नई राजनीतिक भूमिका में सामने आएगा, यह भविष्य तय करेगा।



7

हिमालय की गोद में बसा भारत का शांत और सुंदर राज्य सिक्किम आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में विकास के नए अध्याय लिख रहा है। जून 2024 में सिक्किम विधानसभा चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) को 32 में से 31 सीटों पर ऐतिहासिक विजय दिलाकर लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले प्रेम सिंह तमांग ने पिछले एक वर्ष में सिक्किम को विकास, सुशासन और सांस्कृतिक गौरव के नए शिखर पर पहुंचाया है। यह केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री तमांग की नीतियों और उनके नेतृत्व पर सिक्किम की जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है। यह जनादेश दिखाता है कि सिक्किम की जनता का उन पर भरोसा कितना गहरा है।

सिक्किम के स्वर्णिम युग के शिल्पकार

प्रेम सिंह तमांग

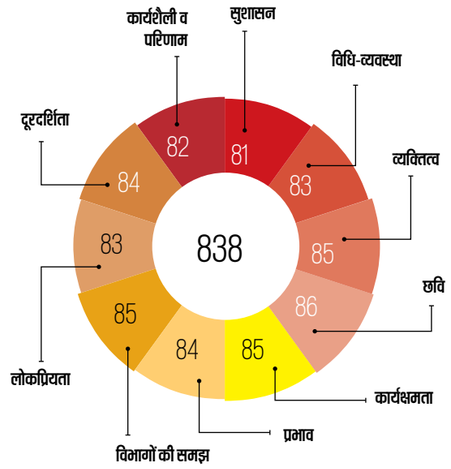
जनता का अभूतपूर्व भरोसा



प्रेरक

स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल

महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री तमांग की सरकार ने 30 से 65 वर्ष की लगभग 1.5 लाख महिलाओं के लिए संपूर्ण राज्य में एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) स्क्रीनिंग कार्यक्रम की घोषणा की, जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक अग्रणी कदम है। इसके साथ ही सिक्किम मणिपाल स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा कार्ड और आयुष्मान भारत के तहत वितरण कार्यक्रम निरंतर जारी हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना जैसी पहलों ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं।



स्वर्ण जयंती: पचास वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव

16 मई 2025 को सिक्किम ने अपने राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने का ऐतिहासिक उत्सव मनाया। मुख्यमंत्री तमांग के नेतृत्व में आयोजित यह स्वर्ण जयंती समारोह केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह सिक्किम की सामूहिक अस्मिता, लचीलेपन और समावेशी विकास की गाथा का उत्सव था। "सुनौलो सिक्किम, समृद्ध सिक्किम, अनी समर्थ सिक्किम" के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री तमांग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के अनुरूप राज्य के भविष्य की दिशा तय की। 29 मई 2025 को पल्जोर स्टेडियम, गंगटोक में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जो यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार का सिक्किम के प्रति कितना आत्मीय जुड़ाव है। इस अवसर पर भारतीय डाक द्वारा स्मारक डाक टिकट और भारत सरकार टकसाल, कोलकाता द्वारा ₹ 50 का स्मारक चांदी सिक्का जारी किया गया। "विजिट सिक्किम" मोबाइल ऐप, एआर गेम्स, टाइम कैप्सूल और "रन फॉर यूनिटी" मैराथन जैसी पहलों ने युवाओं को इस उत्सव से सीधे जोड़ा।

मुख्यमंत्री तमांग ने इस अवसर पर गर्व से रेखांकित किया कि सिक्किम भारत का पहला जैविक (ऑर्गेनिक) राज्य है, जलवायु अनुकूलन में अग्रणी है, सांप्रदायिक सौहार्द का आदर्श मॉडल है, और देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। भूटिया, लेप्चा, नेपाली और अन्य समुदायों के बीच सामाजिक सद्भाव बनाए रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण में हुई परिवर्तनकारी प्रगति उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

विकसित सिक्किम @2047: दूरदर्शी बजट प्रबंधन

मुख्यमंत्री तमांग, जो वित्त विभाग का प्रभार भी स्वयं संभालते हैं, ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन में असाधारण दक्षता दिखाई है। मार्च 2025 में उन्होंने विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए ₹16,196 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा, खेल और संस्कृति के लिए विशेष प्रावधान करते हुए योग एवं मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सीएम मेरिट छात्रवृत्ति योजना और शैक्षिक भ्रमण जैसी पहलों को बढ़ावा दिया गया। इसके एक वर्ष बाद, 20 जुलाई 2026 को उन्होंने वर्ष 2026-27 के लिए ₹19,215



करोड़ का और भी बड़ा बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। इस बजट को "विकसित सिक्किम @2047" के दीर्घकालिक विजन के साथ जोड़ते हुए बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री तमांग ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार एक ऐसी विकास नीति पर काम कर रही है जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संतुलन भी सुनिश्चित हो — यह संतुलन ही उनकी नीति निर्माण की पहचान है।

शिक्षा में नई ऊंचाइयां

शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री तमांग की सरकार ने युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हाल ही में जेईई और नीट जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा की शुरुआत की गई, ताकि आर्थिक बाधाएं किसी भी प्रतिभाशाली छात्र के सपनों के आड़े न आएं। यह मुख्यमंत्री तमांग की उस सोच को दर्शाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर विद्यार्थी का अधिकार है, चाहे वह किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से हो। राज्य के शिक्षकों के उत्कृष्ट योगदान को भी राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली — पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डिकलिंग की रसायन विज्ञान शिक्षिका सुषमा तमांग को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री तमांग ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई दी।

सीमावर्ती राज्य के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा में भूमिका

चीन सीमा से सटे सामरिक महत्व के राज्य के रूप में मुख्यमंत्री तमांग ने बार-बार सिक्किम की राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने में अटूट भूमिका को रेखांकित किया है। अनुच्छेद 371एफ और सिक्किम सब्जेक्ट स्टेटस के तहत मिले संवैधानिक संरक्षणों की रक्षा करते हुए उन्होंने राज्य की परंपराओं, भूमि अधिकारों और स्वायत्तता को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जो पूर्व राजतंत्र की विरासत से मिली सामाजिक संरचना की नींव पर टिके हैं।



सहकारिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति

मार्च 2026 में मुख्यमंत्री तमांग की सरकार ने सिक्किम राज्य सहकारी नीति 2026 का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके साथ ही सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन जैसी नवाचारी पहलों के माध्यम से किसानों को हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों से मुक्त, पर्यावरण-अनुकूल आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये पहलें सिक्किम की जैविक राज्य की पहचान को और सुदृढ़ करती हैं।

सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक पहचान

मुख्यमंत्री तमांग के नेतृत्व में सिक्किम ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी नई पहचान बनाई है। मार्च 2026 में आयोजित सिक्किम अंतरराष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव (SIFF) में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने इस आयोजन को गौरवान्वित किया, जिसमें सिक्किम को पहली बार ऐसा अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन कराने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त सिक्किम के युवा खिलाड़ियों ने भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राज्य का नाम रोशन किया, जिन्हें मुख्यमंत्री तमांग ने व्यक्तिगत रूप से सम्मानित और प्रोत्साहित किया।

निरंतरता और नवाचार का संगम

पिछला एक वर्ष मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है — स्वर्ण जयंती के गौरवशाली उत्सव से लेकर रिकॉर्ड बजट आवंटन तक, महिला स्वास्थ्य में क्रांतिकारी पहल से लेकर छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग तक, और सहकारिता नीति से लेकर अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच तक। तीसरी बार प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में लौटे मुख्यमंत्री तमांग यह साबित कर रहे हैं कि एक छोटा पहाड़ी राज्य भी देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, प्रथम जैविक राज्य का दर्जा और सतत विकास लक्ष्यों में अग्रणी स्थान जैसी उपलब्धियों के साथ राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है। "सुनौलो सिक्किम, समृद्ध सिक्किम, समर्थ सिक्किम" का उनका संकल्प आज हर सिक्किमवासी के जीवन में साकार होता दिख रहा है।



8

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना आज देश के सबसे तेजी से विकसित होते राज्यों में शुमार हो चुका है। पिछले एक वर्ष में उनकी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक सुधारों और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में ऐसी मिसालें कायम की हैं, जिन्होंने तेलंगाना को न केवल दक्षिण भारत बल्कि पूरे देश के लिए एक विकास मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की "तेलंगाना राइजिंग-2047" की दूरदर्शी सोच आज ठोस नीतियों और उपलब्धियों के रूप में साकार होती दिख रही है।

तेलंगाना को समृद्धि के शिखर पर ले जाता जनहितैषी नेतृत्व

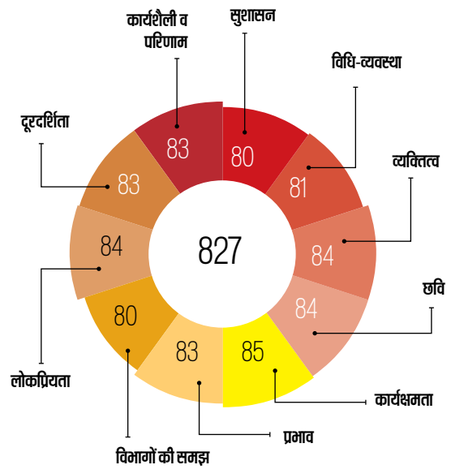
रेवंत रेड्डी

समृद्धि और मानवीय भावनाओं का अद्भुत संयोग



आवास और बुनियादी ढांचे में केंद्र के साथ सहयोग

सितंबर 2026 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत तेलंगाना के लिए पहली किस्त में दो लाख घरों को मंजूरी दी, जिस पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र का आभार व्यक्त किया — यह दर्शाता है कि उनकी सरकार राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए पक्की छत सुनिश्चित करने हेतु केंद्र के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम कर रही है।



रिकॉर्ड बजट: विकास और कल्याण का संतुलन

20 मार्च 2026 को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में कांग्रेस सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश किया, जिसका आकार ₹3,24,234 करोड़ रहा — जो पिछले वर्ष के ₹3.04 लाख करोड़ के बजट से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वृद्धि दर 2025-26 में 10.7 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। इसी उपलब्धि पर गर्व करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि 2024-25 में तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ ₹3.79 लाख तक पहुंच गई, और आरबीआई की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश का नंबर-1 राज्य बन गया है — यह उपलब्धि कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ती है।

देश की सबसे बड़ी फसल ऋण माफी

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सबसे साहसिक और किसान-हितैषी पहलों में से एक रही है फसल ऋण माफी योजना। उनकी सरकार ने ₹20,000 करोड़ खर्च कर 25.5 लाख किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त किया — जो देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी फसल ऋण माफी है। इसके साथ ही किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का श्रेय भी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार को ही जाता है। आदिवासी किसानों के लिए भी उनकी सरकार ने विशेष पहल की — ₹12,600 करोड़ के परिव्यय वाली सौर ऊर्जा सिंचाई योजना के माध्यम से 2.1 लाख आदिवासी किसानों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसे 2029-30 तक 100 प्रतिशत सब्सिडी के साथ लागू किया जाएगा।

महिलाओं को करोड़पति बनाने का संकल्प

महिला सशक्तीकरण मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक रहा है। जून 2026 में तेलंगाना गठन के 12वें स्थापना दिवस पर उन्होंने गर्व से घोषणा की कि महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹ 60,000 करोड़ के शून्य-ब्याज ऋण दिए गए हैं, ताकि



दीर्घकालिक दृष्टि: तेलंगाना राइजिंग-2047

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दीर्घकालिक सोच है। जून 2025 में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार अगले दस वर्षों में तेलंगाना को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे तेलंगाना देश को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में शीर्ष योगदानकर्ता राज्य बन सके। "तेलंगाना राइजिंग" के मंत्र के साथ प्रजा सरकार न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी तेलंगाना को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ठोस योजनाएं तैयार कर रही है।

तेलंगाना की महिलाएं देश के औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकें। मई 2025 में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में महिला त्वरण कार्यक्रम (WAP) और ग्रासरूट यूथ इनोवेशन प्रोग्राम (GYIP) की शुरुआत की, जिनका लक्ष्य एक करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाना और युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, मुफ्त बस यात्रा योजना के माध्यम से महिलाओं ने अब तक कुल 10,000 करोड़ से अधिक यात्राएं पूरी कर आर्थिक बचत की है — यह योजना महिलाओं की गतिशीलता और आत्मनिर्भरता को सीधे प्रभावित कर रही है।

शिक्षा में क्रांतिकारी निवेश

शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार ने अभूतपूर्व निवेश किया है। जहां पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार ने 2023-24 में शिक्षा के लिए मात्र ₹19,093 करोड़ आवंटित किए थे, वहीं कांग्रेस सरकार ने इसे लगातार बढ़ाते हुए 2024-25 में ₹21,292 करोड़, 2025-26 में ₹23,108 करोड़ और 2026-27 में ₹26,647 करोड़ तक पहुंचा दिया — यानी तीन वर्षों में शिक्षा बजट में ₹7,554 करोड़ की वृद्धि। सितंबर 2026 में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की, जो विशेष रूप से Gen Alpha और Gen Beta पीढ़ी की जरूरतों पर केंद्रित है। सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षा पर



जोर देते हुए नर्सरी से कक्षा 12 तक छात्रों और शिक्षकों के लिए मिड-डे मील व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिसके लिए केंद्रीकृत किचन विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री का लक्ष्य वार्षिक बजट में शिक्षा के आवंटन को बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक पहुंचाना है। सितंबर 2026 में ही सरकार ने अपने 32 महीने के कार्यकाल में शुल्क प्रतिपूर्ति (फीस रिएम्बर्समेंट) के रूप में ₹3,488 करोड़ का भुगतान कर छात्रों की उच्च शिक्षा को सुगम बनाया है।

हैदराबाद: वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में उभार

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना ने आईटी और तकनीकी क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। हाल ही में जारी सरकार की "हजार दिन" उपलब्धि रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 में तेलंगाना का आईटी निर्यात ₹3.97 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है और प्रत्यक्ष आईटी रोजगार की संख्या 12.14 लाख तक पहुंच गई है। हैदराबाद में आज 355 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) मौजूद हैं, और अकेले 2026 में 40 नए केंद्रों ने हैदराबाद को अपना गंतव्य चुना। राज्य को डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम मेधा (AI) के क्षेत्र में देश के सबसे तेजी से बढ़ते केंद्रों में शामिल किया गया है — यह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उस दूरदर्शिता का प्रमाण है जिसने हैदराबाद को वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद ठिकाना बनाया है।

जनकल्याण और आर्थिक विकास का आदर्श मॉडल

पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने यह साबित किया है कि किसानों के हित, महिलाओं का सशक्तीकरण, शिक्षा में निवेश और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व — ये सभी लक्ष्य एक साथ, एक ही सरकार के नेतृत्व में हासिल किए जा सकते हैं। देश की सबसे बड़ी फसल ऋण माफी से लेकर प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय नेतृत्व तक, और हैदराबाद के वैश्विक तकनीकी केंद्र बनने से लेकर महिलाओं के लिए ऐतिहासिक ऋण सहायता तक — हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार ने ठोस और मापनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। उनकी स्पष्ट दृष्टि और जनकल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता यह भरोसा दिलाती है कि तेलंगाना "तेलंगाना राइजिंग-2047" के अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से अग्रसर है।



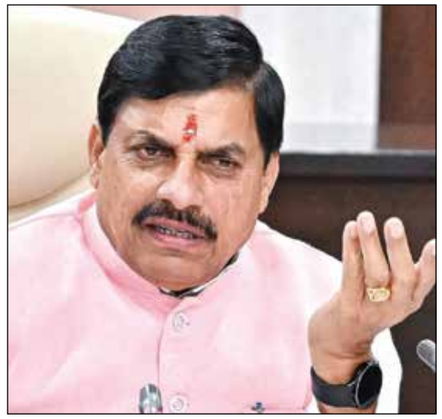
9

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश आज निवेश, औद्योगिक विकास, महिला सशक्तीकरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। पिछले एक वर्ष में उनकी सरकार ने न केवल रिकॉर्ड बजट पेश किया, बल्कि निवेश आकर्षण से लेकर जनकल्याण तक हर मोर्चे पर ऐसी ठोस उपलब्धियां हासिल की हैं जो मध्य प्रदेश को "विकसित मध्यप्रदेश 2047" के लक्ष्य के करीब ले जा रही हैं।

मध्य प्रदेश को निवेश और विकास के शिखर पर ले जाता नेतृत्व

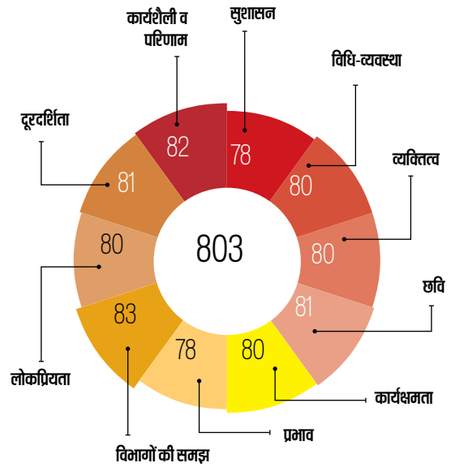
डॉ. मोहन यादव

विकास और पर्यावरण का अद्भुत संतुलन



बुनियादी ढांचा: भोपाल मेट्रो का शुभारंभ

दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के साथ भोपाल में मेट्रो का शुभारंभ किया — यह प्रदेश की राजधानी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जो शहरी परिवहन को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसी अवसर पर विश्व हिंदू आर्थिक मंच के मुंबई सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और राज्य सरकार निवेशकों की हर संभव मदद करने को तत्पर है, ताकि "मेक इन इंडिया" और "विकसित भारत" के संकल्प को साकार किया जा सके।



रिकॉर्ड बजट: विकास का नया आयाम

18 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया, जिसका आकार ₹4,38,317 करोड़ रहा — यह मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला डिजिटल बजट भी था। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य की जीएसडीपी 2026-27 में ₹18,48,274 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 10.69 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि 2011-12 से 2025-26 तक प्रदेश की जीएसडीपी में औसतन 12.73 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, और राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही पहली बार अधोसंरचना विकास के लिए ₹1 लाख करोड़ से अधिक का पूंजीगत प्रावधान किया गया — जो दीर्घकालिक विकास के प्रति मुख्यमंत्री की गंभीरता को दर्शाता है। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि लगातार दूसरे वर्ष सरकार ने किसी नए कर या कर दर में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं रखा — यह वित्तीय अनुशासन और जनहित के प्रति मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

निवेश की नई लहर: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता

मुख्यमंत्री मोहन यादव की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही है निवेश आकर्षण। फरवरी 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) में मध्य प्रदेश को ₹30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, और सरकार के अनुसार इनमें से ₹10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश अब तक वास्तविक धरातल पर उतर चुका है। यह क्रम रुका नहीं — 2026 के पहले छह महीनों में ही ₹76,862 करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 82,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। जुलाई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स-2026 और निवेश सत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश को ₹20,193 करोड़ के अतिरिक्त निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे 27,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की यह दूरदर्शिता सितंबर 2026 में और स्पष्ट हुई, जब वे दुबई में आयोजित AIM कांग्रेस-2026 में वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित करने पहुंचे और वहां चेन्नई सहित कई शहरों में रोड शो आयोजित किए। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ "कंधे से



समृद्धि और संतुलन का आदर्श मॉडल

पिछले एक वर्ष में डॉ. मोहन यादव ने यह साबित किया है कि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण एक साथ, संतुलित रूप से हासिल किए जा सकते हैं। हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने ठोस और मापनीय प्रगति दर्ज की है। उनकी स्पष्ट दृष्टि, वित्तीय अनुशासन और जनकल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता यह भरोसा दिलाती है कि मध्य प्रदेश "विकसित मध्यप्रदेश @2047" के अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से अग्रसर है।

कंधा मिलाकर" खड़ी रहेगी और उनके प्रस्ताव सरकारी दफ्तरों में अटकने नहीं दिए जाएंगे। इसी सिलसिले में दुबई की एक प्रमुख कंपनी से ₹450 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला, और मुख्यमंत्री ने आगामी जनवरी 2027 में भोपाल में होने वाली अगली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS-2027) के लिए निवेशकों को न्योता भी दिया।

महिला उद्यमिता: आत्मनिर्भरता की मिसाल

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला सशक्तीकरण को अपनी सरकार की प्राथमिकता बनाया है। जून 2026 में "सशक्त उद्यमी-समृद्ध मध्यप्रदेश समिट" में उन्होंने बताया कि देश में संचालित लगभग 7 करोड़ MSME इकाइयों में से 25 लाख से अधिक अकेले मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं, और इनमें से 4 लाख 41 हजार से अधिक इकाइयों का नेतृत्व महिला उद्यमी कर रही हैं — यह प्रदेश में महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता का सबसे सशक्त उदाहरण है। इसी अवसर पर उन्होंने उद्योगपतियों के खातों में ₹1,500 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि सीधे ट्रांसफर की। इसके साथ ही लाड़ली बहना योजना के तहत नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि को ₹250 बढ़ाकर ₹1,500 करने की स्वीकृति दी गई — यह मुख्यमंत्री की उस संवेदनशीलता को दर्शाता है जो प्रदेश की हर बहन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जल गंगा संवर्धन अभियान: पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी

मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक



अभूतपूर्व मिसाल कायम की है। 19 मार्च से 30 जून 2026 तक चले 100-दिवसीय "जल गंगा संवर्धन अभियान-2026" के तहत लगभग ₹10,000 करोड़ रुपये की लागत से 3 लाख 62 हजार से अधिक जल संरचनाओं का पुनरुद्धार किया गया। मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि इन प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश देश के बड़े राज्यों में जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान अब वर्षा जल संचयन, नालों की सफाई और नदियों के पुनर्जीवन की दिशा में आगे बढ़ेगा — यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री की दृष्टि केवल तात्कालिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं, बल्कि दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन पर केंद्रित है।

युवाओं और खेल के लिए प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री मोहन यादव युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश के 7,400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी वितरित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं युवाओं से संवाद किया। खेल के क्षेत्र में भी उनकी सरकार सक्रिय है — अक्टूबर 2026 में भोपाल के अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए ₹18.74 करोड़ की मंजूरी दी गई, जिसमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड जैसी एशिया की छह प्रमुख टीमें हिस्सा लेंगी — यह मध्य प्रदेश को खेल जगत के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 2027 को "युवा कल्याण वर्ष" घोषित करने का भी ऐलान किया है।

विकसित मध्यप्रदेश @2047: दूरदर्शी विजन

मुख्यमंत्री मोहन यादव की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दीर्घकालिक दृष्टि है। "GYAN" मॉडल — गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी — पर आधारित उनका बजट दर्शन केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि एक स्पष्ट विकास दर्शन का दस्तावेज है। उनका लक्ष्य है कि 2047 तक राज्य की जीएसडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे और प्रति व्यक्ति आय ₹22 लाख रुपये से अधिक हो। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने रोलिंग बजट की अवधारणा को लागू किया, जो दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की सरकार पारंपरिक ढांचों से आगे बढ़कर नवाचार को अपनाने में कभी पीछे नहीं रहती।

10

पूर्वोत्तर भारत का सुरम्य राज्य मेघालय आज मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा के नेतृत्व में विकास की एक नई और निर्णायक यात्रा पर अग्रसर है। सितंबर 2025 से सितंबर 2026 तक के इस एक वर्ष में उनकी सरकार ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन और उद्यमिता के हर क्षेत्र में ऐसी दूरदर्शी योजनाएं आगे बढ़ाई हैं, जिन्होंने मेघालय को केवल राजधानी शिलांग तक सीमित न रखकर गारो, खासी और जयंतिया हिल्स के दूरस्थ कोनों तक विकास पहुंचाया है। यह वर्ष मुख्यमंत्री संगमा की उस सोच का प्रमाण है कि सच्चा विकास तभी सार्थक है जब वह राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

मेघालय को नई उड़ान देने वाला दूरदर्शी नेतृत्व

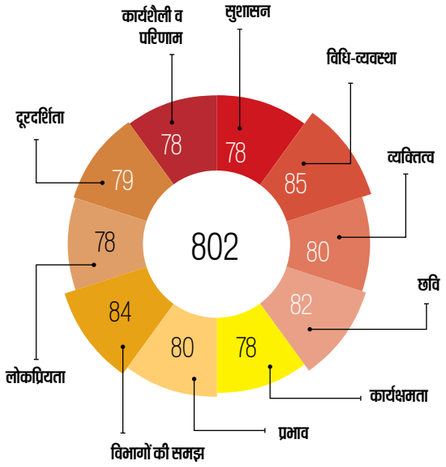
कॉनराड के. संगमा

अपनी मेहनत से दी विरासत को नई पहचान



युवाओं के लिए खेल अवसंरचना

मई 2026 में नॉर्थ गारो हिल्स के डामास में मिनी स्टेडियम की आधारशिला के साथ मुख्यमंत्री संगमा ने 2028 तक 510 खेल अवसंरचना परियोजनाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा है, जो जिला और ब्लॉक स्तर तक युवाओं को अवसर देने की उनकी व्यापक सोच को दर्शाता है।



अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व छलांग

मुख्यमंत्री संगमा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है मेघालय को देश के सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल कराना। फरवरी 2026 में बजट-पूर्व चर्चा के दौरान उन्होंने गर्व के साथ बताया कि राज्य वास्तविक जीएसडीपी वृद्धि के मामले में देश में अग्रणी है। जून 2026 में आयोजित NEIINFRA 2026 में उनकी सरकार ने बताया कि राज्य का बजट पिछले वर्षों में लगभग दोगुना हो चुका है, जबकि पूंजीगत व्यय में लगभग छह गुना की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। सड़क अवसंरचना में लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश उनकी दीर्घकालिक दूरदृष्टि का प्रमाण है। 2026-27 के बजट में राज्य की जीएसडीपी 76,320 करोड़ रुपये आंकी गई, और मुख्यमंत्री संगमा ने 2032 तक इसे 1.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। राज्य का अपना कर राजस्व भी 2017-18 के मात्र 1,450 करोड़ रुपये से बढ़कर आज लगभग 4,226 करोड़ रुपये हो चुका है, जो उनके कुशल वित्तीय प्रबंधन का स्पष्ट प्रमाण है।

कनेक्टिविटी: पहाड़ों की चुनौती का समाधान

भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण इस पर्वतीय राज्य में कनेक्टिविटी को मुख्यमंत्री संगमा ने अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। शिलांग एयरपोर्ट के रनवे को 1,829 मीटर से बढ़ाकर 2,400 मीटर करने की दिशा में भूमि की पहचान का कार्य पूरा किया गया है, जिससे बड़े वाणिज्यिक विमानों का संचालन संभव होगा। बालजेक एयरपोर्ट को पुनर्जीवित करने और शिलांग-तुरा हवाई संपर्क को नियमित बनाने के प्रयास भी सक्रिय रूप से जारी हैं। शिलांग और तुरा में दो नए हेलीपोर्ट का निर्माण उनकी सरकार की सुदूर क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

शहरी यातायात की समस्या से निपटने के लिए जून 2026 में मुख्यमंत्री ने पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत पांच इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। नए प्रशासनिक शहर Mawdiangdiang और शिलांग के बीच बेहतर संपर्क तथा न्यू शिलांग टाउनशिप सहित 32 गांवों के लिए जलापूर्ति परियोजना भी इसी व्यापक शहरी नियोजन का हिस्सा है, जो दिखाता है कि मुख्यमंत्री संगमा भविष्य की जरूरतों को आज ही ध्यान में रखकर योजनाएं बना रहे हैं।



विकास का समग्र मॉडल

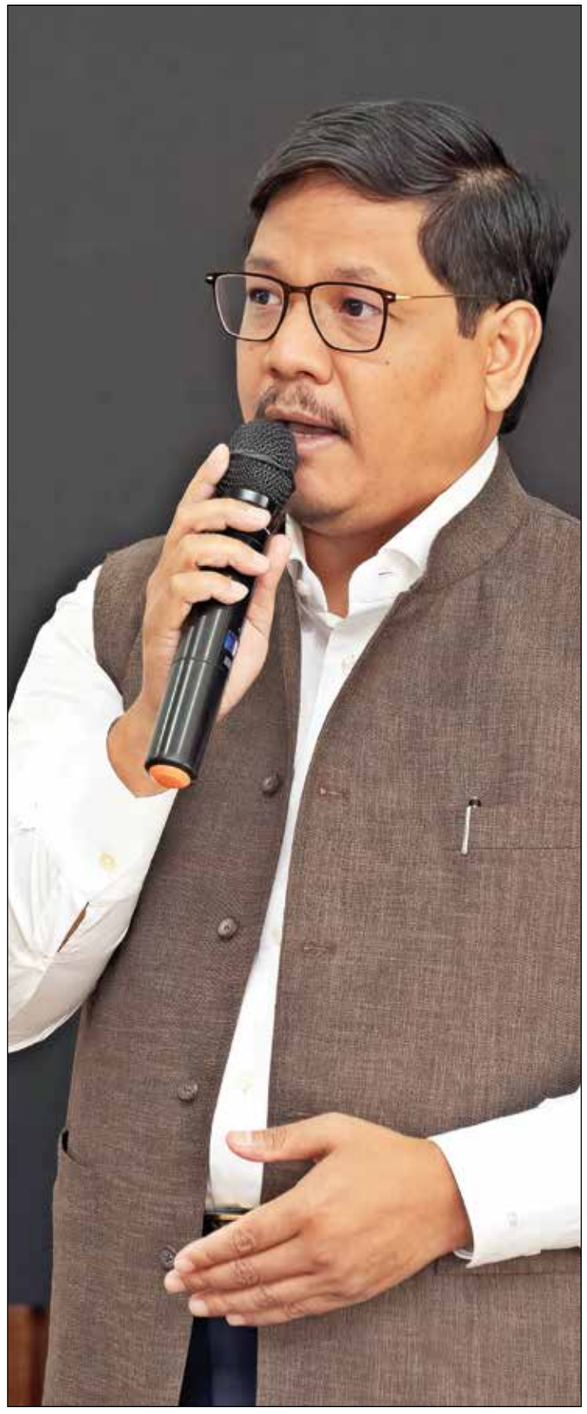
पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने यह साबित किया है कि भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद दूरदर्शी नेतृत्व किसी भी राज्य को विकास के शिखर पर पहुंचा सकता है। बुनियादी ढांचे से लेकर स्वास्थ्य तक, शिक्षा से लेकर कृषि तक, और उद्यमिता से लेकर पर्यटन तक — हर क्षेत्र में उनकी सरकार ने ठोस और मापनीय प्रगति दर्ज की है। तेज आर्थिक वृद्धि, बढ़ता पूंजीगत व्यय और स्थानीय संसाधनों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की रणनीति यह भरोसा दिलाती है कि मेघालय मुख्यमंत्री संगमा के नेतृत्व में एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर मजबूती से अग्रसर है।

अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाएं

मुख्यमंत्री संगमा के लिए स्वास्थ्य सेवा का अर्थ केवल बड़े अस्पताल नहीं, बल्कि गांव-गांव तक चिकित्सा की पहुंच है। सितंबर 2026 में उन्होंने स्वयं समीक्षा करते हुए बताया कि पिछले दो वर्षों में 110 से अधिक सब-सेंटर पूरे किए जा चुके हैं, और मार्च 2027 तक 200 और सब-सेंटर पूरे करने का लक्ष्य है, जिसके बाद राज्य में इनकी कुल संख्या 700 तक पहुंच जाएगी। बजेंगडोबा, बर्नीहाट, महेंद्रगंज, रक्सामग्रे जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन अंतिम चरण में है, और रेसुबेलपारा के 100-बेड अस्पताल को सक्रिय करने की तैयारी है। सितंबर 2026 में तीन मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत यह साबित करती है कि मुख्यमंत्री संगमा तकनीक आधारित समाधानों से दूरदराज इलाकों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

शिक्षा और बाल कल्याण में मिसाल

शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री संगमा की सरकार ने पारदर्शिता और गति दोनों पर ध्यान दिया है। अगस्त 2026 में 96,812 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की पहली किस्त जारी की गई, और SPARSH आधारित रियल-टाइम व्यवस्था से भुगतान में देरी को समाप्त किया गया। 2,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, दो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का पूर्ण होना और 29 अन्य का निर्माण कार्य उनकी शिक्षा-केंद्रित सोच का प्रमाण है। कैप्टन विलियमसन संगमा



स्टेट यूनिवर्सिटी और राज्य के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी संस्थाओं का विकास उच्च शिक्षा में मेघालय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

बच्चों के कुपोषण के विरुद्ध मुख्यमंत्री संगमा की संवेदनशीलता 2026-27 के बजट में स्पष्ट झलकती है, जहां 1,000-दिन के मिशन के लिए 127 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। 4.3 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही पूरक पोषण कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, और 600 नए आंगनवाड़ी केंद्र-सह-क्रेच बनाने की योजना उनकी सरकार की बाल कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाती है।

किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प

मुख्यमंत्री संगमा ने कृषि को केवल उत्पादन तक सीमित न रखते हुए मूल्यवर्धन की रणनीति अपनाई है। मई 2026 में उमस्ली में कम्युनिटी बायोचार प्लांट का उद्घाटन मिट्टी के स्वास्थ्य और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक नवाचारी पहल है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है जुलाई 2026 में शुरू हुआ Mission Golden Spice — 175.45 करोड़ रुपये की यह पांच वर्षीय परियोजना मेघालय की जीआई-टैग लाकाडोंग हल्दी को वैश्विक बाजार से जोड़ेगी। इस मिशन के तहत 2030 तक खेती का क्षेत्र 2,500 से बढ़ाकर 7,500 हेक्टेयर करने और किसानों को मिलने वाला मूल्य लगभग तीन गुना, यानी 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंचाने का लक्ष्य है — यह मुख्यमंत्री संगमा की किसान-हितैषी सोच का बेजोड़ उदाहरण है।

उद्यमिता, पर्यटन और जल सुरक्षा में नई दिशा

फरवरी 2026 में 15 देशों के खरीदारों और 300 से अधिक स्थानीय एमएसएमई को जोड़ते हुए Reverse Buyer-Seller Meet का आयोजन तथा 'MeghaRise' ब्रांड का शुभारंभ स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक मंच देने की दिशा में मुख्यमंत्री संगमा की दूरदर्शिता का परिचायक है। नवंबर 2025 में सोहरा इंटीग्रेटेड टूरिज्म सर्किट की आधारशिला और 233 करोड़ रुपये के DoNER प्रोजेक्ट्स स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने की उनकी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। मार्च 2026 में Jal Jeevan Mission 2.0 के तहत सुधार-आधारित समझौते पर हस्ताक्षर के साथ राज्य में 83 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण नल जल कवरेज हासिल करना उनकी सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धि है।

Sardar Vallabhbhai Patel
International Airport Ahmedabad

Vietnam Airlines
REACH FURTHER

From the City of Kites to the
Land of Lotus.

Welcoming
Vietnam Airlines
to Ahmedabad.

फेम इंडिया

सोच बदलें, समाज बदलेगा



मुख्यमंत्री पंचरत्न 2026

फेम इंडिया -एशिया पोस्ट सर्वे



कर्तव्यनिष्ठ

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर संगठनात्मक कार्य, प्रशासनिक अनुभव और विकास-केंद्रित राजनीति का उदाहरण रहा है। 22 जुलाई 1970 को नागपुर में जन्मे फडणवीस ने छात्र राजनीति से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। वे नागपुर के महापौर रहे और महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करते गए। वर्ष 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2022 में उपमुख्यमंत्री और 5 दिसंबर 2024 को तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके सामने देश के सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में शामिल महाराष्ट्र की आर्थिक गति बनाए रखने, रोजगार बढ़ाने, कृषि संकट कम करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की चुनौती है।

विकास, निवेश और आधुनिक महाराष्ट्र का रोडमैप

देवेंद्र फडणवीस

तकनीक और भविष्य के उद्योगों पर नजर

फडणवीस सरकार महाराष्ट्र को नई तकनीक और स्टार्टअप का केंद्र बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश और लगभग 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य सामने रखा गया। सरकार छह एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टार्टअप के लिए आधुनिक कंप्यूटिंग सुविधाएं विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। फिलहाल फडणवीस सरकार महाराष्ट्र को देश की अग्रणी आर्थिक शक्ति बनाए रखने के लिए एक व्यापक विकास रोडमैप पर काम कर रही है।

निवेश और औद्योगिक विकास पर जोर

राज्य को देश का प्रमुख निवेश गंतव्य बनाए रखने के लिए औद्योगिक परियोजनाओं, विदेशी निवेश और रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है। मुंबई, पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और नासिक जैसे शहरों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ नए निवेश केंद्र विकसित करने की कोशिश है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को भविष्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जा रहा है।

बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का विस्तार

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, समृद्धि महामार्ग, मुंबई मेट्रो और अटल सेतु जैसी परियोजनाएं राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा हैं। नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग से विदर्भ और मराठवाड़ा को मुंबई के आर्थिक क्षेत्र से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार का जोर बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों तक भी बेहतर परिवहन सुविधाएं पहुंचाने पर है।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान

महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को गति देने, जल संरक्षण, कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन और किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। नमो शेतकरी महासन्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से पात्र किसानों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को भी विकास की व्यापक रणनीति से जोड़ा गया है।

महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जारी है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता दी जाती है। 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 26,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता और रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

किसानों के लिए राहत और आधुनिक कृषि

किसानों को राहत देने के लिए 2026 के बजट में दो लाख रुपये तक की कृषि ऋण माफी की घोषणा महत्वपूर्ण रही। नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना के लिए 6,060 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली योजना भी लागू है। इसके साथ ही कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल, सौर पंपों और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम हो रहा है।



कर्मयोद्धा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी 2025 को पदभार संभालते हुए एक ऐसी यात्रा शुरू की, जिसने 27 वर्षों बाद राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नई पहचान दी। पूर्व डूसू अध्यक्ष और शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की चौथी भाजपा मुख्यमंत्री बनीं, और यह साबित किया है कि दिल्ली को वर्षों से जिस स्थिर, समाधान-उन्मुख नेतृत्व की तलाश थी, वह अब उन्हें मिल चुका है।

दिल्ली को 27 साल बाद मिला नया विकास मॉडल

रेखा गुप्ता

रिकॉर्ड बजट: विकास और राहत का संगम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। बजट भाषण में उन्होंने गर्व से बताया कि 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय देश में तीसरी सबसे अधिक है और यह 5,31,610 रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप व साइकिल जैसी घोषणाओं ने उनकी प्राथमिकता को दर्शाया है।

पहली बार दिल्ली का अलग राज्य खाता

15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री गुप्ता ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि साझा की — पहली बार दिल्ली के राज्य खाते का पृथक्करण हुआ है और पहली बार भारतीय रिज़र्व बैंक को दिल्ली का आधिकारिक बैंकर बनाया गया है। यह सुधार दिल्ली के विकास कार्यों के लिए धन की उपलब्धता और वित्तीय प्रबंधन को कहीं अधिक मजबूत बनाएगा।

यमुना की सफाई: वर्षों पुराना सपना साकार होता हुआ

मुख्यमंत्री गुप्ता की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक रही है यमुना की सफाई की दिशा में ठोस कार्य। उनकी सरकार ने यमुना सफाई के लिए 27 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) शुरू किए हैं — यह उस समस्या का व्यावहारिक समाधान है, जिसे दशकों से केवल राजनीतिक बहस का विषय बनाकर रखा गया था। मुख्यमंत्री गुप्ता ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार समस्याओं की चर्चा नहीं, बल्कि समाधान में विश्वास रखती है।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति: भारत की EV सिटी बनती दिल्ली

पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता की सरकार ने एक व्यापक EV पॉलिसी लॉन्च की, जिसके तहत आज दिल्ली के पास देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बसों की फ्लीट में से एक मौजूद है। मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि दिल्ली तेजी से भारत की EV सिटी के रूप में उभर रही है — यह प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ राजधानी बनाने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

कौशल विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा

फरवरी 2026 में कैबिनेट ने "मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना" को मंजूरी दी, जिसकी शुरुआत ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 18,000 दर्जियों से होगी, जिसके बाद कुम्हार, बढ़ई, मोची जैसे अन्य शिल्पकारों को भी इससे जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने वर्तमान कार्यकाल में 10,000 से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने और 4 लाख रोजगार सृजित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा।

स्वास्थ्य सेवा में संवेदनशील दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री गुप्ता ने स्वास्थ्य को केवल आंकड़ों तक सीमित न रखते हुए इसे मानवीय संवेदना से जोड़ा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का सही अर्थ है कि जब किसी गरीब परिवार में बीमारी आए, तो उसे इलाज के लिए अपना घर, जमीन या गहने बेचने की नौबत न आए — यह सोच उनकी सरकार की स्वास्थ्य नीतियों की बुनियाद बनी है।

सुदृढ़ शासन, ठोस बदलाव

रिकॉर्ड बजट से लेकर यमुना की सफाई तक, वित्तीय सुधारों से लेकर ईवी क्रांति तक, और कारीगरों के सम्मान से लेकर स्टार्टअप के भविष्य तक — हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री गुप्ता ने ठोस और दृश्यमान परिणाम दिए हैं। यह भरोसा दिलाता है कि दिल्ली अब वास्तविक विकास और सुशासन के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है।



कर्मठ

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में केंद्रशासित प्रदेश ने पिछले एक वर्ष में लोकतांत्रिक शासन और आर्थिक पुनर्निर्माण की एक नई यात्रा शुरू की है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली निर्वाचित सरकार का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने यह साबित किया है कि जम्मू-कश्मीर की जनता को उनके नेतृत्व में स्थिर, जवाबदेह और विकासोन्मुख शासन मिल रहा है।

जम्मू-कश्मीर में उम्मीद और विकास की नई इबारत

उमर अब्दुल्ला

कर्मठ

सात वर्षों बाद निर्वाचित सरकार का पहला बड़ा बजट

फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,13,767 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें 80,640 करोड़ राजस्व व्यय और 33,127 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया — यह सात वर्षों में किसी निर्वाचित सरकार द्वारा पेश किया गया पहला पूर्ण बजट होने के गौरव को आगे बढ़ाता है। कृषि क्षेत्र के लिए 815 करोड़ के आवंटन से लगभग 2.88 लाख रोजगार सृजित करने, दो-फसली खेती को बढ़ावा देने और बागवानी तथा ऊन-चमड़ा उद्योग को मजबूत करने की योजना बनाई गई है — यह मुख्यमंत्री की उस सोच को दर्शाता है कि आर्थिक विकास आम किसान और कारीगर तक पहुंचना चाहिए।

"सुरक्षा अर्थव्यवस्था" से आगे: उद्यमिता आधारित विकास का विजन

अगस्त 2026 में बेंगलुरु में IIMBUE सम्मेलन में मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने अपनी सरकार के विकास दर्शन को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य निवेश और उद्यमिता के लिए अनुकूल माहौल बनाकर जम्मू-कश्मीर को दशकों पुरानी, संघर्ष-प्रेरित "सुरक्षा अर्थव्यवस्था" से आगे ले जाना है। उन्होंने रेखांकित किया कि स्थायी खुशहाली केवल सरकारी खर्च पर नहीं, बल्कि भरोसे, स्थिर संस्थानों और विश्वसनीय शासन पर टिकी होती है। अपने दादा व पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के "हलधर को जमीन" जैसे ऐतिहासिक भूमि सुधारों का हवाला देते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारें सड़कें, स्कूल और अस्पताल बना सकती हैं, लेकिन स्थायी आर्थिक विकास तभी संभव है जब लोगों को भरोसा हो कि उनके प्रयासों को अवसर और सफलता मिलेगी — यह दूरदर्शी सोच उनकी सरकार की आर्थिक नीति की बुनियाद बन चुकी है।

प्रशासनिक सुधार और युवाओं की सफलता

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला की सरकार ने कारोबारी सुगमता को प्राथमिकता देते हुए मार्च 2026 में "अनुपालन किफायत 2.0" की व्यापक समीक्षा की, जिससे जम्मू-कश्मीर में व्यापार करना आसान बनाया जा सके। इसी माह जम्मू-कश्मीर के 17 उम्मीदवारों ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 उत्तीर्ण की, जिन्हें उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने व्यक्तिगत रूप से बधाई दी — यह प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा और मुख्यमंत्री की शिक्षा-प्रोत्साहन नीतियों का प्रमाण है।

संपर्क और राष्ट्रीय एकीकरण

कश्मीर रेल परियोजना के उद्घाटन को मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के कार्यकाल की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा गया, जिसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ी छलांग बताया गया। यह परियोजना जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से और गहराई से जोड़ती है।

जनता के अधिकारों के लिए मुखर आवाज़

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल दिलाने के लिए भी निरंतर सक्रिय रहे हैं। जुलाई 2026 में उन्होंने जम्मू में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान इस मांग को उठाने की घोषणा की — यह उनकी उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वे प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं की आवाज़ हर लोकतांत्रिक मंच पर बुलंद करते रहेंगे।

संघर्ष और सुशासन का संगम

पिछला एक वर्ष मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के लिए स्थिरता, सुधार और आशा का वर्ष रहा है। रिकॉर्ड बजट से लेकर उद्यमिता आधारित विकास मॉडल तक, प्रशासनिक सुधारों से लेकर युवाओं की उपलब्धियों तक — उनकी सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि जम्मू-कश्मीर अब संघर्ष की छाया से निकलकर विकास और समृद्धि के नए युग की ओर मजबूती से बढ़ रहा है।



सक्रिय

15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में जन्मे भूपेंद्रभाई रजनीकांत पटेल पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। वर्ष 2017 में वे पहली बार घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 13 सितंबर 2021 को विजय रूपाणी के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद दोबारा इस पद की जिम्मेदारी संभाली। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य गुजरात को निवेश, उद्योग, तकनीक और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए 2047 तक विकसित गुजरात के लक्ष्य की ओर ले जाना है।

निवेश, आधुनिक बुनियादी ढांचे और विकसित गुजरात का रोडमैप

भूपेंद्र पटेल

सक्रिय

महिला, बालिका और सामाजिक कल्याण

महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा तथा पोषण के लिए नमो लक्ष्मी योजना, नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना और नमो श्री योजना जैसी पहलें जारी हैं। नमो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना है, जबकि नमो सरस्वती योजना विज्ञान विषयों में आगे बढ़ने वाली छात्राओं को सहायता देती है।

निवेश और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर

गुजरात लंबे समय से देश के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्रों में शामिल रहा है। भूपेंद्र पटेल सरकार ने इस पहचान को नई तकनीक और उभरते उद्योगों के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष तकनीक, डेटा सेंटर, जहाज निर्माण और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए नीतियां बनाई गई हैं।

क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी

राज्य के सभी हिस्सों में विकास का लाभ पहुंचाने के लिए छह क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं। इनके तहत उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र, तटीय सौराष्ट्र, कच्छ और सूरत क्षेत्र में उनकी जरूरतों के अनुसार बुनियादी ढांचा विकसित करने की योजना है। मार्च 2026 में सूरत आर्थिक क्षेत्र के सड़क नेटवर्क को उन्नत करने के लिए 1,185 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई। इनमें 383 किलोमीटर लंबाई के 24 सड़क कार्य शामिल हैं।

युवाओं के लिए कौशल और रोजगार

युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। 2026-27 के बजट में नमो गुजरात कौशल एवं रोजगार मिशन के लिए 226 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराना है।

हरित ऊर्जा और तकनीकी नवाचार

गुजरात सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भूपेंद्र पटेल सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल विकास को भविष्य की आर्थिक रणनीति का हिस्सा बनाया है। 2026 में राज्य की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026-31 सामने आई। इसके अलावा डेटा सेंटर नीति 2026-29 तथा स्पेसटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की नीतियां भी घोषित की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य तकनीकी निवेश, अनुसंधान और उच्च कौशल वाले रोजगार को प्रोत्साहित करना है।

भविष्य की तैयारी और प्रशासनिक सुधार

अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए तैयार करना भी राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में है। इसके लिए खेल सुविधाओं, शहरी परिवहन और आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सरल और डिजिटल बनाने के लिए सुगम डिजिटल गुजरात जैसी पहलें आगे बढ़ाई जा रही हैं। गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (GRIT) के माध्यम से दीर्घकालिक विकास योजनाओं और उनके परिणामों की निगरानी की व्यवस्था विकसित करने का प्रयास है।

भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात की विकास नीति में उद्योग, निवेश, तकनीक, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई देती है।



व्यवहारिक

भरतपुर जिले के अटारी गांव में 15 दिसंबर 1966 को जन्मे भजनलाल शर्मा ने संगठन की राजनीति से अपना सफर शुरू किया। 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में पानी की उपलब्धता, रोजगार, किसानों की आय, औद्योगिक विकास और प्रदेश के दूरदराज के इलाकों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है।

विकास के नए रोडमैप के साथ राजस्थान को बदलने की कोशिश

भजनलाल शर्मा

औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास

राजस्थान को निवेश और उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। फरवरी 2026 में प्रस्तुत राज्य बजट का आकार 6,10,956 करोड़ रुपये रखा गया। सरकार ने 2028-29 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन के दौरान हुए लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के समझौतों में से करीब 8 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वयन के चरण में पहुंच चुकी हैं।

रोजगार और युवा सशक्तीकरण पर जोर

मुख्यमंत्री कार्यालय की जानकारी के अनुसार, सरकार के कार्यकाल में अब तक 1.93 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी थीं। लगभग 1.18 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जबकि करीब 1.25 लाख पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। युवाओं को गांवों में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अटल ज्ञान केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इनमें पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी और ई-मित्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

सड़क और आधारभूत ढांचे का विस्तार

राजस्थान सरकार के आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 37,527 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 51,790 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है। इनमें 18,917 किलोमीटर नई सड़कें शामिल हैं। ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 1,760 गांवों और 21 ढाणियों को पक्की सड़कों से जोड़ने की जानकारी भी सरकार ने दी है।

पानी की समस्या के समाधान की दिशा में प्रयास

राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश के लिए जल प्रबंधन हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। भजनलाल शर्मा सरकार ने रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौते और अन्य अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने लगभग 12,500 करोड़ रुपये के निवेश से सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की योजना आगे बढ़ाई है। 65,308 सरकारी स्कूलों का तकनीकी सर्वेक्षण कराया जा चुका था। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए चिकित्सा संस्थानों, नर्सिंग कॉलेजों और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया है।

महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 18 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं, जबकि 25 हजार स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सोलर दीदी के रूप में जुड़ी हैं।

आर्थिक विकास के साथ सामाजिक जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने किसानों, श्रमिकों और ग्रामीण परिवारों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी जोर दिया है। अक्टूबर 2026 में सरकार की ओर से बताया गया कि 76 लाख से अधिक किसानों को 14,400 करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में दिए जा चुके हैं।

राजस्थान की विकास यात्रा को देख कर कहा जा सकता है कि प्रदेश का नेतृत्त्व एक योग्य व कुशल हाथों में है।

इंपैक्ट फीचर



देश के हिन्दू तीर्थ स्थलों में बिहार के मधुबनी जिला मुख्यालय के निकट मंगरौनी गांव स्थित एकादश रुद्र महादेव का अलग ही महत्व है. ये महत्व इसलिये भी बढ़ जाता है कि यह अपने आप में दुनिया में अनोखी जगह है, जहां एक साथ शिव के विभिन्न रूपों 11 शिवलिंगों का दर्शन व पूजन का अवसर मिलता है. यहां शिव 11 रूपों महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम देवदेवा, भदोद्भव एवं कपालिश्च के दर्शन का सौभाग्य शिव भक्तों को विशेष तौर पर मिलता है.

मधुबनी में स्थापित है एकादश रुद्र महादेव का दुर्लभ मंदिर

इसके अलावा इस एकादश रुद्र मंदिर परिसर में विष्णु के विभिन्न अवतारों, श्री विद्या यंत्र, विष्णुपद गया क्षेत्र, महाकाल, महाकाली, गणेश सरस्वती आदि साथ ही आम एवं महुआ का आलिंगन-बद्ध वृक्ष, भगवान शिव, पार्वती, महा-लक्ष्मी, महा-सरस्वती यंत्र, विष्णु-पादुका आदि के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है.

इस परिसर स्थित पीपल वृक्ष का भी तांत्रिक महत्तम अलग ही है. कहते हैं कि इसके स्पर्श मात्र से भूत प्रेत के प्रभाव से लोगों को मुक्ति मिल जाती है. वहीं श्री विद्या यंत्र के दर्शन व पूजन से लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों की कृपा बनी रहती है.

सोमवार के दिन यहां भंडारे का आयोजन किया जाता है, इस दिन यहां रुद्राभिषेक एवं षोडषोपचार पूजन करते हैं तो उनकी इच्छित मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं. पंडित जी बताते हैं कि यहां एक ही शक्ति-वेदी पर स्थापित शिव के सभी एकादश रुद्र लिंग रूपों में 10 मई से 21 मई 2000 ई. के बीच विभिन्न तरह की आकृतियां उभर आयीं.

1 महादेव – विगत 30 जुलाई 2001 को अर्द्ध-नारीश्वर का रूप प्रकट हुआ है. कामाख्या माई का ये भव्य रूप है. पांचवें सोमवारी के दिन गणेश जी गर्भ में प्रकट हुए. शिवलिंग पर ये रूप स्पष्ट नजर आती है.

2 शिव – प्रभु श्री राम ने कहा था कि मैं ही शिव हूं. इस लिंग में सिंहासन का चित्र उभरा है, जो प्रभु श्री राम का सिंहासन दर्शाता है.

3 रुद्र – भय को हराने वाले इस लिंग में बजरंगबली पहाड़ लेकर उड़ रहे है बड़ा ही अद्भुत चित्र प्रकट हुआ है.

4 शंकर – गीता के दसवें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही शंकर हूं. इस लिंग में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, बांसुरी और बाजूबंध स्पष्ट दृष्टिकोण होता है.

5 नील लोहित– जब महादेव ने विषपान किया था, तब उनका नाम नील लोहित पड़ गया था. इस लिंग में सांप एवं ऊँ का अक्षर प्रकट हुआ है.

6 ईशान – हिमालय पर निवास करने वाले महादेव जिसे केदारनाथ कहते हैं विगत नौ जुलाई 2001 सावन के पहले सोमवार को राजराजेश्वरी का रूप प्रकट हुआ.

7 विजय – इस शिवलिंग में छवि बन रही है जिस कारण आकृति अस्पष्ट है.

8 भीम – महादेव का एक रूप भी है. इस शिवलिंग में गदा की छवि उभर कर सामने आयी है. गदा का डंडा अभी धीरे-धीरे प्रकट हो रहा है.

9 देवादेव – ये लिंग सूर्य का रूप है. इस शिवलिंग में गदा के नीचे दो भागों से सूर्य की किरणें फूटकर शीर्ष में मिल रही है.

10 भवोद्भव – इस लिंग में उमा शंकर की आकृति प्रकट हुई है. दोनों आकृतियां धीरे-धीरे बढ़ रही है.

11 कपालिश्च– महादेव का एक रूप बजरंगबली है. बजरंगबली ब्रह्मचारी थे, इसलिये संभवतः इस लिंग में कोई चित्र नहीं उभर रहा है.

> कांची पीठ के शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल व अधीक्षण पुरातत्व-विद डॉ. फणीकांत मिश्र आदि आये तो यहां शिव के एकादश रुद्र का अलौकिक रूप देख भाव विह्वल हो गये. उन्होंने कहा कि ये अपने आप में धार्मिक दृष्टिकोण से अद्वितीय पूजन व तीर्थ स्थल है.

किसी दिन ये शिवलिंग अपने आप पूरा लाल हो जायेगा.

बाबा जी का कहना है कि सभी शिव भक्तों को मात्र एक बार आकर इन शिवलिंगों उभरी हुई आकृतियों को देखे तो पता लगेगा कि ऐसे शिवलिंग विश्व में कहीं भी नहीं हैं

गौरतलब है कि प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित मुनीश्वर झा ने 1953 ई. में यहां शिव मंदिर की स्थापना की थी. इस मंदिर में स्थापित सभी शिवलिंग काले ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं जिनका प्रत्येक सोमवार शाम को दूध, दही, घी, मधु, पंचामृत, चंदन आदि से स्नान होता है. श्रृंगार के लिये विशेष तौर पर कोलकाता से कमल के फूल मंगाये जाते हैं. प्रधान पुजारी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान करने नहीं गया नहीं जा पाते उनके लिये यहां गया क्षेत्र बना है जहां पिण्डदान कर मुक्ति पायी जाती है.





Umashree

Foundation

(To creat Endless Happiness)



Address -
F Block - sector -50
Noida -201304 (Delhi NCR)

Contact - +91-9911976808
Email ID - ss.fameindia@gmail.com

Instagram - @ra.jshree4866

Express India®
Courier and Cargo
Domestic and International

Fast • Reliable • Everywhere



BLUE DART | DHL

Blue Dart DHL Express
Sales Associate - Chanchal

Fast Delivery
Safe & Secure Handling
Worldwide Network
Real-Time Tracking
24/7 Customer Support

Unit No. 101, Ground Floor,
Assotech Business Cresterra
Sector 135, Noida – 201304

9310958552 /
9555606783

'Your Trusted Courier Partner'

विरासत का मान, विकास का अभियान
प्रयागराज

अतुल्य आस्था उत्सव प्रदेश

प्रयागराज में 11 मंदिर कॉरिडोर विकसित

हनुमान मंदिर कॉरिडोर, अक्षयवट मंदिर-सरस्वती कूप कॉरिडोर एवं भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर से पर्यटन को विस्तार

यमुना नदी घाट पर पौराणिक कथाओं पर आधारित वॉटर लेजर शो

गंगा एक्सप्रेसवे का 16 कि.मी. हिस्सा जनपद में स्थित



विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP